छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 215 ■ अम्बिकापुर, गुरूवार 20 अगस्त 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

शासन को 67.15 लाख की क्षति पहुंचाने वाले जिला परियोजना समन्वयक सहित 2 गिरफ्तार

एसीबी ने 15 साल पूर्व 2.70 करोड़ के स्कूल फर्नीचर खरीदी घोटाले में की कार्रवाई

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अविभाजित सरगुजा जिले की पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए खरीदी गए फर्नीचर में हुए बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। 15 साल पुराने इस प्रकरण में आर्थिक अनियमितता कर शासन को 67.15 लाख रुपये की क्षति पहुंचाने के आरोप में एसीबी ने तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक सत्यप्रकाश पाण्डेय और फर्म संचालक संजय पटेल को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

बता दें कि, कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान अंबिकापुर को सूरजपुर

और बलरामपुर-रामानुजगंज क्षेत्र की पूर्व माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर खरीदी के लिए 2.70 करोड़ रुपये का आवंटन मिला था। तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के अनुमोदन के बाद सीएसआईडीसी की दरों पर पंजीकृत फर्मों को क्रय आदेश दिए गए थे। एसीबी की विवेचना में सामने आया कि संजय पटेल द्वारा संचालित मेसर्स दर्शन फेब्रिकेशन और आकृति प्रिंटिंग प्रेस चोपड़ापारा ने बिना फर्नीचर सप्लाई किए ही फर्जी बिल बना दिए। इन्हीं बिलों के आधार पर शासकीय राशि निकाल ली गई। जांच में यह भी पाया गया कि संजय पटेल अपना कमीशन काटने के बाद बची हुई राशि तत्कालीन डीपीसी सत्यप्रकाश पाण्डेय को देता था, इस संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस मिलीभगत से शासन को कुल 67 लाख 15 हजार 814 रुपये का नुकसान हुआ। अन्य आपूर्ति कर्ताओं की भूमिका, वास्तविक आपूर्ति और कमीशन की राशि के संबंध में अग्रिम विवेचना जारी है।

2017 में दर्ज हुआ था केस

इस संबंध में वर्ष 2017 में अपराध क्रमांक 28/2017 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। लंबी विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर अब कार्रवाई की गई है। जांच में यह भी पर्दाफास हुआ कि अन्य फर्मों ने भी आपूर्ति में गड़बड़ी की और तत्कालीन डीपीसी ने उनसे भी कमीशन लिया है। अन्य आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका की जांच अभी जारी है।

मामले में अग्रिम जांच जारी

बुधवार को पुलिस ने आरोपी सत्यप्रकाश पाण्डेय, तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक और संजय पटेल, संचालक दर्शन फेब्रिकेशन को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। दोनों पर धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 120-बी, 420, 409 आईपीसी के तहत केस दर्ज है। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण में अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

टावर से 2 लाख से ज्यादा की बैटरी और तार चोरी

छ.ग.फ्रंटलाइन रामानुजनगर। थाना क्षेत्र के गणेशपुर स्थित बीएसएनएल टावर से अज्ञात चोरों ने 5 बैटरी और तार चोरी कर ली, जिसकी कीमत 2 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। टावर में इंजीनियर के पद पर पदस्थ विशाल तिवारी पिता दिनेश तिवारी निवासी ग्राम तारा ने इसकी शिकायत थाना रामानुजनगर में की है। उन्होंने बताया है कि 05.07.2026 की रात 1 से 6 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने टावर का घेराव तोड़कर बैटरी केबिनेट का ताला काटा और 5 नग बैटरी व बैटरी का तार चोरी करके ले गए, जिसमें बीएसएनएल को 2 लाख 2 हजार रुपये से अधिक की क्षति पहुंची है। घटना की जानकारी टावर में तैनात गार्ड महेंद्र सिंह ने दी थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है, और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

केंद्रीय जेल में हुई निबंध प्रतियोगिता

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सेवा किटी समूह द्वारा केंद्रीय जेल मं आयोजित निबंध प्रतियोगिता में इग्नू केंद्र के 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कल्याण अधिकारी बानी मुखर्जी ने किया। निबंध का विषय स्वतंत्र भारत में युवा आक्रोश का कारण और निदान था।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पैर के ट्यूमर की जटिल सर्जरी

एक वर्ष से परेशान युवक को मिली राहत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। उत्तर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जटिल सर्जरी की सुविधा मिलने से अब गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर नहीं करना पड़ेगा। एमआरआई की सुविधा मिलने के बाद अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने पैर में ट्यूमर से करीब एक वर्ष से परेशान ऐसे ही एक युवक की सफल सर्जरी की, जिससे उसे राहत मिली है।

जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के ब्रह्मरोड निवासी हरिशंकर सोनी 27 वर्ष के पैर में पिछले एक साल से बड़ा ट्यूमर था। ट्यूमर शरीर के

महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं और नसों के बेहद करीब और उनसे चिपका हुआ था। ऐसे जटिल मामलों में पहले मरीजों को बेहतर जांच और ऑपरेशन के लिए रायपुर रेफर किया जाता था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध होने से मरीज का विस्तृत प्री-ऑपरेटिव मूल्यांकन संभव हो सका। एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर पूरी सर्जिकल प्लानिंग की गई और ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद किए गए हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण में यह ट्यूमर श्वानोमा पाया गया। डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज न होने पर इससे नसों को गंभीर नुकसान हो सकता था। अस्पताल अधीक्षक डॉ. आरसी आर्या के मार्गदर्शन में की गई सफल सर्जरी में डॉ. पी.आर. शिवहरे, डॉ. मनोज भारती, पीजी डॉ. शुभम और लक्ष्मीकांत की टीम ने अहम भूमिका निभाई।

मरीजों के बाहर जाने की नहीं बनेगी नौबत

मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा सही निदान के साथ बेहतर इमेजिंग, बारीक सर्जिकल प्लानिंग व जटिल सर्जरी भी अब अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संभव है। एमआरआई और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से अब संभाग के मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मरीज और स्वजन ने बेहतर जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की टीम का आभार जताया है।

कोर्ट के आदेश के बाद भी लाठी-टांगी का भय दिखाकर जोत डाला खेत

दो किसानों की रिपोर्ट पर 27 लोगों के विरूद्ध नामजद केस दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन रेवटी/सूरजपुर। जिले के ग्राम नरोला में जमीन विवाद को लेकर 27 लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग अपराध दर्ज किया गया है। आरोप है कि कोर्ट के स्थायी निषेधाज्ञा के बावजूद आरोपियों ने लाठी-टांगी और हल-बैल लेकर किसानों की जमीन पर जबरन जोताई कर धान बो दिया। पुलिस चैकी रेवटी में ग्राम नरोला निवासी शिवप्रसाद पिता सुंदर 65 वर्ष और राय सिंह पिता बालमुकुंद 50 वर्ष ने अलग-अलग शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने सभी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

आवेदकों का कहना है कि आवेदकों के अनुसार उनकी कुल 10.97 हेक्टेयर जमीन है। व्यवहार न्यायालय प्रतापपुर ने वर्ष 2019 में उनके पक्ष में डिक्री पारित कर कब्जे में दखल पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी बालचंद पिता रामगरीब सहित गांव के 26 अन्य लोगों ने 16.06.2026 को सुबह 8 बजे हाथों में लाठी-टांगी और हल-बैल लेकर मनवारी दोहर की जमीन पर अवैध अतिचार कर जोताई शुरू कर दी। मना करने पर सभी गाली-गलौज करके जमीन पर आने पर काटकर टुकड़ा-टुकड़ा करके फेंक देने की धमकी दी। नायब तहसीलदार डांडकरवा से मौके की जांच भी कराई गई, जिसमें आरोपियों द्वारा जोताई करना पाया गया। पुलिस ने दोनों किसानों की शिकायतों पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 190, 191(2), 296, 329(3), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है, और वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

इनके विरूद्ध अपराध दर्ज

बालचंद 65 वर्ष, ओमप्रकाश 30 वर्ष, रामलाल 40 वर्ष, सोनू 35 वर्ष, चंदन 35 वर्ष, सूरज 22 वर्ष, श्यामलाल 35 वर्ष, हरिनाथ 45 वर्ष, रामशरण 35 वर्ष, चुटी 25 वर्ष, राजेश 35 वर्ष, लालू 25 वर्ष, धरम सिंह 40 वर्ष, रामरूप 50 वर्ष, बैजनाथ 70 वर्ष, देवप्रकाश 35 वर्ष, अवध 45 वर्ष, देवप्रकाश 30 वर्ष, चंदर 50 वर्ष, धनराज 60 वर्ष, महाबीर 50 वर्ष, राय सिंह 40 वर्ष, ओमप्रकाश 25 वर्ष, रामप्रसाद 45 वर्ष, जिरबोधन 50 वर्ष, कमल 35 वर्ष, प्रेमलाल 30 वर्ष, सभी निवासी ग्राम नरोला।

संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना भाजपा का संकल्प: नारायण चंदेल

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत बुधवार को सर्किट हाउस में माटी युक्त पवित्र कलश वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र माटी युक्त कलश को शक्तिकेंद्र व बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यह अभियान केवल माटी वितरण नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और संत परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समानता, भाईचारे और श्रम की गरिमा का संदेश दिया। उनके विचारों को युवाओं तक पहुंचाना जरूरी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि यह संकल्प संतों और महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक ले जाने का अभियान है। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने संत रविदास के छुआछूत विरोधी विचारों का उल्लेख किया। जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' का संदेश आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में कृष्णकांत चन्द्रा, प्रबोध मिंज, विश्वविजय सिंह तोमर, हरपाल सिंह भामरा, कमलभान सिंह मरावी, फुलेश्वरी सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। संभाग प्रभारी संतोष दास ने बताया कि 30 अगस्त तक कलशों का पूजन कर मंदिर परिसर में तुलसी रोपण किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन विनोद हर्ष ने किया।

के आर टेक्निकल कॉलेज
SINCE 2008
(Regular | Private | Distance)
ADMISSION OPEN 2026-27
मान्यताएँ
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से सम्बद्ध
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त
इग्नू का स्टडी सेंटर
SINCE 2008
COURSES OFFERED
UG COURSES: BCA, BBA, BCOM, BSC BIO, BSC MATHS, BSC CS, BA
PG COURSES: MSC CS, MSC IT, MSC BOTANY, MSC ZOOLOGY, MSC CHEMISTRY, MSC MATHS, MSC PHYSICS, MCOM, MSW, MA HINDI
PROFESSIONAL COURSES: DCA, PGDCA, PGDBM, PGDRD, BLIB
SCHOLARSHIP FACILITIES
विद्यासागर छात्रवृत्ति (सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए)
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC, ST एवं OBC विद्यार्थियों हेतु)
सीमित कोर्स में फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध
COLLEGE CAMPUS: अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन के पास, काली घाट मंदिर के आगे, संजय नगर, छत्तीसगढ़
9926513170, 9826612781
CITY OFFICE: कृष्ण आभा भवन, रिंग रोड, नमना कला, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़
9826183771

पहले पुल टूटा, अब भारी बारिश में अस्थायी एप्रोच बह गया

दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित, जगन्नाथपुर-खंडगवां मार्ग पर आवागमन ठप

छ.ग.फ्रंटलाइन जरही। जगन्नाथपुर-खंडगवां मार्ग पर स्थित सुखाड़ पुल के टूटने के बाद क्षेत्रवासियों की परेशानी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन और प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बनाया गया अस्थायी रपटा भी पहली ही बारिश में पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही रपटा को जोड़ने वाली एप्रोच सड़क का एक हिस्सा भी बह गया है। इससे मार्ग पर आवागमन एक बार फिर प्रभावित हो गया है।

सुखाड़ पुल के क्षतिग्रस्त होने से पहले ही जगन्नाथपुर, सुखदेवपुर, सोनगरा, खड़गवां सहित आसपास के कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित हो चुका था। ग्रामीणों और राहगीरों की परेशानी को देखते हुए पास में अस्थायी रपटा तैयार किया गया था, जिसके जरिए दोपहिया और हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हुआ था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इससे कम से कम रोजमर्रा का आवागमन सुचारु रहेगा, लेकिन भारी बारिश के कारण तेज बहाव में रपटा को जोड़ने वाली एप्रोच सड़क ही बह गई। ग्रामीणों का कहना है कि अस्थायी रपटा नाममात्र के लिए राहत साबित हुआ है। हल्की बारिश में ही एप्रोच रोड के बह जाने से इसके निर्माण और प्रबंधन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों, व्यापारियों की परेशानी बढ़ी

मार्ग बाधित होने का सीधा असर क्षेत्र के लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों, व्यापारियों और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। मार्ग बंद होने से कोयला परिवहन से जुड़े लोगों और स्थानीय व्यवसायियों की गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।

करीब 2.07 करोड़ की लागत से बना था सुखाड़ पुल

गौरतलब है कि, वर्ष 2015 में करीब 2.07 करोड़ रुपये की लागत से सुखाड़ पुल का निर्माण कराया गया था। पुल का एक हिस्सा हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों और राहगीरों की सुविधा के लिए पुल के पास ही अस्थायी रपटा बनाया गया था। इससे भी कुछ समय तक इस रपटा से लोगों का आना-जाना हुआ। इससे ग्रामीणों के सामने आवागमन का संकट और गहरा गया है।

ग्रामीणों ने की तत्काल मरम्मत और पक्के पुल की मांग

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि एप्रोच मार्ग की तत्काल मरम्मत कराकर आवागमन बहाल किया जाए। साथ ही सुखाड़ पुल के स्थान पर नए पक्के पुल का निर्माण शुरू कराया जाए, ताकि बरसात के दौरान हर साल पैदा होने वाली आवागमन की समस्या से ग्रामीणों को स्थायी राहत मिल सके। फिलहाल भारी बारिश के बीच ग्रामीण और कोयला परिवहन से जुड़े लोग मार्ग के दुरुस्त होने तथा पक्के पुल के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्थायी इंतजाम के भरोसे क्षेत्र की बड़ी आबादी को लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता।

जिला स्तरीय संयुक्त मॉक अभ्यास घुनघुटा बांध में आज

नागरिकों से आपदा प्रबंधन की तैयारियों में सहयोग की अपील

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2026-27 के अंतर्गत सरगुजा जिले में जिला स्तरीय संयुक्त मॉक अभ्यास का आयोजन आज 20 अगस्त को किया जाएगा। यह मॉक अभ्यास प्रातः 10 बजे श्याम घुनघुटा डेम लिबरा (दरिमा) में आयोजित होगा। मॉक अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना तथा आपदा प्रबंधन के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करना है। जिला स्तरीय मॉक अभ्यास के लिए अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक को नोडल अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर बन सिंह नेताम को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मॉक अभ्यास के सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक दायित्व सौंपे गए हैं। पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा बल एवं यातायात व्यवस्था, वनमंडलाधिकारी वनमंडल सरगुजा को बांस-बल्ली की व्यवस्था तथा जल संसाधन संभाग अंबिकापुर को नाव एवं मोटर बोट की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। जिला सेनानी को गोताखोर एवं प्रशिक्षित तैराक, गोताखोर ड्रेस, लाइफ जैकेट, सुरक्षा जाल, फायर ब्रिगेड, डीजल-पेट्रोल, रस्सी एवं बड़ी सीढ़ी सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पंडाल, टेंट एवं माइक व्यवस्था तथा उप संचालक जनसंपर्क को वीडियोग्राफी एवं मीडिया प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सा एवं एंबुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को स्काउट एवं गाइड के छात्र-छात्राओं की मॉक अभ्यास में भागीदारी सुनिश्चित करने तथा प्राचार्य पी.जी. कॉलेज अंबिकापुर को एनसीसी के छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

आपदा प्रबंधन को परखने के लिए आयोजन

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि, मॉक अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार की घबराहट न करें। यह केवल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित किया जा रहा प्रशिक्षणात्मक अभ्यास है।

मेरी पत्नि मर गई...सबको मार दूंगा, कहते हुए बलुवा से हमला

खेल रहे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, 3 घायलों का चल रहा उपचार

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के चलगली थाना अंतर्गत मेरी पत्नी मर गई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा कहते हुए एक युवक ने बलुवा से अंधाधुंध हमला करके 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना ग्राम गढ़ौली ऊपरपारा की है। जानकारी के मुताबिक, 17 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे सुनील पोया निवासी ग्राम कड़िया मोहलीटिकरा हाथ में बलुवा लेकर घूम रहा था, जो पहले घर के सामने खेल रहे संतोष आयाम के नाती कृष्णा आयाम के गर्दन पर बलुवा से वार किया, जब बच्चे को बचाने के लिए गणपत आयाम आई तो उसके पीठ पर भी हमला कर दिया। आरोपी की हरकत को देखकर जब संतोष शोर मचाया तो वह उसकी ओर बलुवा लेकर बढ़ा, जिससे भयभीत होकर वह घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी जो मिलेगा उसको मार दूंगा कहते हुए रोड की ओर निकल गया। आरोपी के जाने के बाद संतोष अपने नाती कृष्णा आयाम को देखने गया, तो वह बेहोश हो गया था और भाभी गणपत भी कराह रही थी। इसके बाद पता चला कि रास्ते में आ रहे मोटरसायकल सवार रामसाय पंडो व पीछे बैठी महिला कमला पंडो को भी आरोपी सुनील बलुबा से लहराकर मारा, जिससे वे गिर गए, और कमला के पसली में चोट लगने के कारण खून बहने लगा। शोर मचाने पर गांव के लोग जमा होने लगे और सुनील भाग गया। डॉयल 112 की मदद से आहत कृष्णा आयाम, गणपत आयाम, कमला पंडो को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्रफनगर ले गये। आरोपी को गांव के लोगों ने दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह जंगल की ओर भाग गया। मामले में अपराध दर्ज करके पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026
ISO 9001: 2015 CERTIFIED
बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।
डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद
समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा
बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

साप्ताहिक बाजार दतिमा में खड़े बाइक को चोरों ने किया पार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। साप्ताहिक बाजार दतिमा में खड़ी बाइक को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया है। करंजी पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत गांगीकोट निवासी 20 वर्षीय रामकुमार पिता सोनसाय मंगलवार की शाम करीब 7 बजे दतिमा साप्ताहिक बाजार अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 डीई 3948 में गया था।

बाइक को बाजार के पास खड़ी कर सामान लेने अंदर गया और जब आधे घंटे बाद वापस लौटा, तब देखा कि बाइक को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया है। सूचना पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

रेलवे आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार में बस चालक गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। रेलवे आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार के मामले में आरपीएफ ने एक और बस चालक को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के क्रम में 19 अगस्त को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अंबिकापुर में समन के आधार पर उपस्थित हुए मनोज कुमार यादव 46 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15 हिरागिरी दफाई, हल्दीबाड़ी चिरमिरी वर्तमान निवासी ग्राम नारायणपुर ककरही, पोस्ट दौलतपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर उप्र से पूछताछ की गई। पूछताछ में मनोज कुमार यादव ने बताया कि वह पिछले करीब दो वर्षों से सिंह बस सर्विस बनारस में चालक के रूप में कार्यरत है। उसके अनुसार अविनाश कुमार जो सिटी पीआरएस बैकुंठपुर का

कर्मचारी है के द्वारा बैकुंठपुर से दिए गए रेलवे आरक्षित टिकटों के लिफाफे को सिंह बस के माध्यम से बनारस में संजय कुमार विश्वकर्मा तक पहुंचाता था। मनोज ने बताया कि प्रत्येक लिफाफे के बदले उसे 200 से 250 रुपए कमीशन मिलता था। वह सप्ताह में करीब दो बार रेलवे के तत्काल आरक्षित टिकटों के लिफाफे बैकुंठपुर से बनारस पहुंचाने का काम करता था।

पूछताछ के दौरान उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे जानकारी थी कि अविनाश कुमार और संजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा रेलवे आरक्षित टिकटों का अवैध कारोबार किया जा रहा है। बावजूद इसके कमीशन के लालच में वह टिकटों को पहुंचाकर उनके अवैध कार्य में सहयोग करता रहा।आरपीएफ द्वारा मनोज कुमार यादव को पूर्व में दर्ज मामले में धारा 143 रेल अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया है। मामले में अब तक आरपीएफ चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अभी मामले में शामिल आरोपियों की पड़ताल के लिए जांच जारी है।

सरस्वती साइकिल योजना से 38 छात्राओं को मिली नि:शुल्क सायकल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयनगर शिक्षा में बुधवार को शासन की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत 38 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। नई साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। छात्राओं ने इसे विद्यालय आने-जाने में सहूलियत के साथ अपनी पढ़ाई को और बेहतर ढंग से जारी रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएमडीसी के पूर्व अध्यक्ष कृष्णपाल बिंझिया उपस्थित रहे।अन्य अतिथियों में

विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती सुफियाना खलखो, भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवधन राम बिंझिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश राजवाड़े, ब्रह्मदेव बिंझिया, सोहन सारथी, शांतनु सिंह चौहान तथा मंडल महामंत्री देवशरण सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। अतिथियों ने छात्राओं को साइकिल प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की नींव भी है। शासन की ऐसी योजनाएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि आवागमन की सुविधा मिलने से उन्हें नियमित रूप से विद्यालय पहुंचने में मदद मिलती है और पढ़ाई बीच में छोड़ने की संभावना भी कम होती है। अतिथियों ने छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर अध्ययन करने तथा अपने लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है। ग्रामीण अंचल में विद्यालय की दूरी कई बार छात्राओं के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में साइकिल योजना उनके लिए आवागमन का साधन उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने का भी माध्यम बन रही है। नई साइकिल हाथ में मिलने से उनके चेहरों पर खुशी और उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम का संचालन उषा बेला खाखा ने किया।

इंजीनियरिंग और ओएचई विभाग में खुलेगा ओवरटाइम रजिस्टर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में इंजीनियरिंग एवं ओएचई विभाग के कर्मचारियों के ओवरटाइम से संबंधित रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के कार्मिक विभाग ने 18 अगस्त को संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि रेलवे मजदूर कांग्रेस के साथ द्वितीय पीएनएम बैठक 2026 के दौरान नए एजेंडा क्रमांक 30 पर चर्चा हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बिलासपुर मंडल के इंजीनियरिंग एवं ओएचई विभाग में ओटी रजिस्टर खोलने का निर्णय लिया गया है।

मंडल कार्मिक विभाग ने वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय तथा वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता टीआरडी सहित संबंधित अधिकारियों से बैठक के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ओवरटाइम रजिस्टर जल्द से जल्द खोलने की अपील की है। इस निर्णय से इंजीनियरिंग एवं ओएचई विभाग में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले ओवरटाइम कार्य का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने और संबंधित प्रविष्टियों को दर्ज करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप मिलने की उम्मीद है।

दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भक्तिभाव से मना गोस्वामी तुलसीदास जयंत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार को रामचरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जयंती कोयलांचल बिश्रामपुर में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। बस स्टैंड स्थित श्री संकटमोचन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में इस अवसर पर अखंड मानस मंडल परिवार द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर गोस्वामी तुलसीदास के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया।

साथ ही गोस्वामी तुलसीदास द्वारा साहित्य और विशेष रूप से रामचरितमानस के माध्यम से समाज को दिए गए संदेशों को महत्वपूर्ण बता आमजन को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति, मर्यादा, भक्ति और नैतिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। सुंदरकांड पाठ पश्चात आरती व प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन में मंदिर के पुजारी भोला महराज, अखंड मानस मंडल के अध्यक्ष गुड्डू महराज, सुरेन्द्र तिवारी, सुरेश सिंह चंदेल, शैलेश चौबे, आनंद चौधरी, पूर्णमासी, महेंद्र राजवाड़े सहित अन्य मानस प्रेमी उपस्थित रहे।

छोटे पांव मजबूत कदम द्वारा बस्तामुक्त विद्यालय में छाता-कापी किया वितरित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। प्रथम बस्तामुक्त शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुनियाडीह में छोटे पांव मजबूत कदम सामाजिक संस्था प्रतापपुर से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमपाल अग्रवाल प्रतापपुर के माध्यम से गोयल टीएमटी रायपुर के सौजन्य एवं मुकेश गर्ग सूरजपुर द्वारा 40 छात्र-छात्राओं को छाता वितरण किया

गया। संस्था प्रमुख सीमांचल त्रिपाठी ने बताया कि इस समय क्षेत्र में हो रही जबरदस्त बारिश एवं बच्चों के भींगकर स्कूल आने एवं बीमार होने से स्कूल प्रतिदिन आने और पूरे समय स्कूल में रहने में परेशानी हो रही थी। बच्चों की इन्हीं परेशानियों को देखकर नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं के लिए 40 नग छाता तथा 300 नग कॉपी की व्यवस्था की गई। इस दौरान एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती कौशिल्या राजवाड़े, उपाध्यक्ष श्रीमती गुड्डी बाई विश्वकर्मा, कौशल्या राजवाड़े, भुवनेश्वर प्रसाद राजवाड़े सहित शिक्षक रिजवान अंसारी, श्रीमती एम. टोप्पो उपस्थित रहे।

ओवरलोड कोयला-राखड़ वाहनों से दहशत में बिश्रामपुर कॉलोनीवासी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर कॉलोनी क्षेत्र में कोयला एवं राखड़ फ्लाई ऐश से लदे ओवरलोड भारी वाहनों के अनियंत्रित आवागमन को लेकर अब लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। घनी आबादी के बीच दिन-रात दौड़ रहे भारी वाहनों के कारण जहां सड़कें जर्जर हो रही हैं, वहीं स्कूली बच्चों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एवं बिश्रामपुर निवासी अभिषेक सिंह सोमु ने कलेक्टर सूरजपुर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पिछले कई महीनों से बिश्रामपुर एसईसीएल कॉलोनी के मुख्य मार्ग से कोयला एवं राखड़ लदे सैकड़ों भारी वाहन गुजर रहे हैं।

इनमें कई वाहन क्षमता से अधिक भार लेकर चलते हैं। इससे सड़क पर दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। खास चिंता की बात यह है कि जिस मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है, उसी रास्ते पर कई प्रमुख शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल स्थित हैं। सुबह स्कूल खुलने और दोपहर बाद छुट्टी के समय इस मार्ग पर छात्र-छात्राओं की भारी आवाजाही रहती है। हजारों बच्चे पैदल, साइकिल, दोपहिया वाहनों तथा अन्य साधनों से इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर शाम के समय आम नागरिकों के साथ धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। सावन माह के चलते धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने से भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रशासन द्वारा कॉलोनी क्षेत्र में नो-एंट्री व्यवस्था लागू किए जाने के बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉलोनी मार्ग को पूर्णतः नो-एंट्री जोन घोषित कर इसका सख्ती से पालन कराने की मांग की है। आवेदन में विशेष रूप से राखड़ परिवहन का मुद्दा उठाया गया है। बताया गया है कि कुछ समय से एनटीपीसी कोरबा से राखड़ लोड कर वाहनों के माध्यम से भटगांव क्षेत्र में डंप किया जा रहा है। आरोप है कि इस कार्य में लगे कई वाहन ओवरलोड रहते हैं और कुछ चालकों के पास आवश्यक वैध दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं होते। इसके बावजूद वाहन निर्धारित रूट के बजाय बिश्रामपुर एसईसीएल कॉलोनी के मुख्य मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। वाहनों पर लगे तिरपाल भी कई बार कटे-फटे अथवा ठीक से ढके हुए नहीं होते हैं। इस कारण राखड़ और कोयले की धूल हवा में उड़ती रहती है, जिससे सड़क किनारे रहने वाले लोगों के साथ राहगीरों को भी परेशानी होती है। भारी वाहनों के लगातार आवागमन से सड़क की स्थिति भी खराब होने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व में भी कॉलोनीवासियों ने ओवरलोड एवं तेज रफ्तार भारी वाहनों को रोककर प्रशासन को सूचना दी थी। जांच के दौरान एक वाहन चालक के नशे में होने तथा आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद मामूली चालान की कार्रवाई कर वाहन को छोड़ दिए गया था। ज्ञापन में दावा किया गया है कि इसी मार्ग पर पूर्व में ओवरलोड वाहनों की चपेट में आने से तीन से चार लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। अभिषेक सिंह ने कलेक्टर से कोयला एवं ओवरलोड राखड़ परिवहन के कारण जर्जर हुई सड़कों की मरम्मत कराने तथा आवश्यक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की भी मांग की है। भारी वाहनों को रिहायशी कॉलोनी से हटाकर निर्धारित वैकल्पिक मार्ग से संचालित कराया जाए। साथ ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर पूर्ण नो-एंट्री लागू कर पुलिस एवं यातायात विभाग के माध्यम से नियमित निगरानी कराई जाए।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को मिल रहा बेहतर मंच

★ कौशल से रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
★ लाइवलीहुड कॉलेज में युवाओं को मिल रहा प्रशिक्षण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में शासन की मंशा के अनुरूप जिले में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला रोजगार अधिकारी के नेतृत्व में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।लाइवलीहुड कॉलेज इसी सोच को धरातल पर साकार करने का माध्यम बन रहा है। जहां प्रशिक्षणार्थियों को उनकी रुचि और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वेल्डिंग और जल संचालक वितरण में प्रशिक्षण

वर्तमान में लाइवलीहुड कॉलेज में वेल्डिंग एवं जल संचालक-वितरण ट्रेड में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत लगभग 30 प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित कार्य की तकनीकी जानकारी के साथ उपकरणों के उपयोग और कार्य की व्यवहारिक बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे युवा रोजगार के साथ स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं।

ट्रैक्टर मैकेनिक का बैच भी होगा शुरू

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आगामी दिनों में ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड का नया बैच प्रारंभ किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को ट्रैक्टर के रखरखाव, सर्विसिंग, तकनीकी खराबियों की पहचान एवं मरम्मत संबंधी व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। इससे ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

प्रशिक्षणार्थियों को मिल रही नि:शुल्क सुविधाएं

लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण के साथ आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए नि:शुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान रहने और भोजन की चिंता नहीं रहती तथा वे पूरी एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण, प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण एवं संसाधन, प्रशिक्षण सामग्री तथा रोजगार एवं प्लेसमेंट संबंधी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सुविधाओं से युवाओं को बेहतर वातावरण में कौशल सीखने का अवसर मिल रहा है।

प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार से जुड़ रहे युवा

लाइवलीहुड कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कुछ युवाओं ने प्रशिक्षण में सीखे हुनर को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं ने स्वयं का कार्य शुरू कर स्वरोजगार की राह अपनाई है। अब तक 287 लोगों को प्रशिक्षण दिया है जिसमें से 217 लोग रोजगार के माध्यम से जुड़े है। प्रशिक्षण से स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवाओं की सफ्लता अन्य प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। अब प्रशिक्षण ले रहे युवा भी अपने हुनर को रोजगार में बदलने और भविष्य में स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्साहित हैं।

शासन-प्रशासन के प्रयासों से कौशल विकास की पहल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो जिले के युवाओं की क्षमता को अवसरों से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे श्री सुरेश कुमार ने बताया कि योजना युवाओं के लिए काफी सार्थक है। वे बताते है कि इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से मिली, जिसके बाद उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज में पंजीयन कराया और प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पहले उनके पास किसी प्रकार का कौशल नहीं होने के कारण रोजगार प्राप्त करने में काफी परेशानी होती थी। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण मिलने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वे कहीं भी रोजगार के अवसर तलाशने के साथ अपने कौशल के माध्यम से स्वरोजगार भी कर सकेंगे।उन्होंने युवाओं को कौशल से जोड़ने की इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसी तरह प्लंबर ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहेश्री कमल गुप्ता ने बताया कि उनके क्षेत्र में प्लंबिंग कार्य की काफी मांग है और उन्हें भी यह काम पसंद था, लेकिन प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी के अभाव में वे इस कार्य को व्यवस्थित रूप से करने में सक्षम नहीं थे। लाइवलीहुड कॉलेज में उन्हें नि:शुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा के साथ प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना प्रशिक्षण पूरा कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे अपने गांव में ही प्लंबिंग का कार्य शुरू कर आजीविका अर्जित करना चाहते हैं। उनके लिए यह प्रशिक्षण अपने गांव में रहकर रोजगार एवं स्वरोजगार का अवसर प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बाढ़ बचाव तैयारियों की टेबल टॉप बैठक सम्पन्न

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रदेश के सभी जिलो में 20 अगस्त को आयोजित होने वाली बाढ़ बचाव मॉक ड्रिल से पूर्व आज राज्य स्तर पर वर्चुअल रूप से बैठक आयोजित की गई। जिसमें बलरामपुर-रामानुजगंज से संयुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में टेबल टॉप बैठक में अपर कलेक्टर श्री चेतन बोरघरिया, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रज्ञा नायक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की एसडीआरएफ की टीम, नगर सेना राजस्व एवं पुलिस प्रशासन सहित संबंधित अधिकारीगण वर्चुअल रूप से जुड़े रहे।

बैठक में बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की रणनीति, विभागीय समन्वय तथा संसाधनों के उपयोग पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में बाढ़ एवं जलभराव जैसी परिस्थितियों के पूर्व तैयारियां, आपदा समय निपटने एवं आपदा पश्चात किए जाने वाले गतिविधियों के बारे में बताया गया। बैठक में बताया गया कि आपदा के समय सभी विभागों को आपसी सहयोग और समन्वय के साथ काम करना होगा जिससे ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके। टेबल टॉप बैठक के दौरान संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पूर्व चिन्हांकन, बाढ़ की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने अस्थाई आश्रय स्थल, राहत शिविरों में प्राथमिक उपचार, गोताखोरों, जल पुलिस, बोट, राफ्ट, तथा राहत शिविरों की व्यवस्थाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

गौरतलब है कि 20 अगस्त को जिला स्तर पर विकासखण्ड रामचन्द्रपुर अंतर्गत बड़ा रघुनाथनगर जलाशय पर बाढ़ बचाव परिदृश्य आधारित मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान राहत एवं बचाव दलों द्वारा विभिन्न परिदृश्यों एवं आपात सेवाओं के प्रबंधन का अभ्यास किया जाएगा।

बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक या बेचेंगे बीमा? एलआईसी प्रचार पोस्ट ने खड़े किए सवाल?

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

वाड्रफनगर।सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी संभाल रहे एक शिक्षक के नाम से सोशल मीडिया ग्रुप में एलआईसी बीमा का प्रचार किए जाने का मामला सामने आया है। पोस्ट सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और शासकीय कर्मचारियों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए स्क्रीनशॉट में अनुपम उपाध्याय के नाम से एलआईसी बीमा का प्रचार करते हुए लिखा गया है–ह्लजिसकी गारंटी नहीं है वह है जिंदगी, जिसकी पूरी गारंटी है वह है एलआईसीह्व आज ही मुझे कॉल करें, आपका बीमा सलाहकार।ह्व इसके बाद ग्रुप में

एक सदस्य ने शिक्षक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ह्लयही है अब वाड्रफनगर के शिक्षक, अब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, यह सिर्फ एलआईसी करेंगे, आदमी का जिंदगी बताएंगे।ह्व पोस्ट में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी टैग कर मामले पर ध्यान देने की बात कही गई है।

पोस्ट डिलीट होने के बाद और बढ़े सवाल

बताया जा रहा है कि संबंधित पोस्ट ग्रुप में प्रसारित होने के बाद उसे डिलीट कर दिया गया। हालांकि, पोस्ट का स्क्रीनशॉट सामने आने से मामला चर्चा में आ गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि संबंधित व्यक्ति शासकीय शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, तो शासकीय सेवा के साथ बीमा प्रचार-प्रसार करने की अनुमति है या नहीं?

शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल

सरकारी शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करना है। ऐसे में यदि कोई शिक्षक निजी व्यावसायिक गतिविधि में संलिप्त होकर उसका प्रचार करता है, तो इसकी वैधानिकता और सेवा नियमों की जांच जरूरी हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा शिक्षक यदि अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के प्रचार में दिखाई देता है, तो शिक्षा विभाग को मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

विभाग से स्पष्ट जवाब की मांग

मामले में शिक्षा विभाग से यह स्पष्ट करने की मांग उठ रही है कि संबंधित शिक्षक को एलआईसी के बीमा प्रचार या एजेंसी से जुड़ी गतिविधि करने की अनुमति है अथवा नहीं। यदि अनुमति नहीं है और सेवा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल वायरल स्क्रीनशॉट के आधार पर मामले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित शिक्षक का पक्ष और शिक्षा विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

20 अगस्त से 'जन संवाद-2.0': ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने की पहल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत के निदेर्शानुसार 20 अगस्त से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के दौरान ₹जन संवाद-2.0 विकसित भारत ग्राम संकल्प₹ का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्राम सभा में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने, ग्रामीणों में जनजागरूकता पैदा करने तथा विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों एवं उद्देश्यों से आमजन को अवगत कराना है।

पांच प्रमुख गतिविधियों का होगा आयोजन

1. ₹मेरे गांव की प्राथमिकता₹ वोटिंग वॉल

- सफेद चार्ट पेपर पर ग्रामीण अपने गांव की आवश्यकताओं

एवं विकास संबंधी प्राथमिकताएं दर्ज करेंगे।

इससे ग्राम स्तर पर विकास की वास्तविक जरूरतों को सामने लाने में मदद मिलेगी।

2. ₹125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार₹ की शपथ

- ग्रामीणों एवं श्रमिकों को रोजगार के अधिकार और योजना के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

3. ₹विकसित भारत संदेश कार्ड₹ के माध्यम से सुझाव

- ग्रामीण सुझाव लिखकर सुझाव पेटी में जमा करेंगे।

प्राप्त संदेशों का रजिस्टर में संधारण किया जाएगा।

4. ₹जनता पूछे-पंचायत बताए₹ संवाद मंच

- ग्रामीण योजना से संबंधित सवाल पूछ सकेंगे और सरपंच-सचिव जवाब देंगे।

इसका उद्देश्य ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान करना है।

5. ₹तिरंगे के साथ विकास संदेश रैली₹

- ग्राम सभा के बाद तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसमें ग्रामीण, श्रमिक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

2 उप अभियंता और 15 प्लेसमेंट कर्मचारियों के नियुक्ति की मांग

नपा अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री को सौंपा पत्र

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां नगर पालिका परिषद में विकास एवं निर्माण कार्यों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े ने जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल को पत्र सौंपकर नगर पालिका में दो उप अभियंताओं की नियुक्ति तथा 15 प्लेसमेंट कर्मचारियों की भर्ती को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। प्रभारी मंत्री को भेजे पत्र में नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि जिला मुख्यालय का नगरीय निकाय होने के कारण जिला प्रशासन के साथ-साथ नगर

पालिका पर भी अतिरिक्त कार्यों का भार है। व्यवस्थाओं के सफल क्रियान्वयन और विकास कार्यों में गति लाने के लिए कम से कम दो उप अभियंता एवं 15 प्लेसमेंट कर्मचारियों की आवश्यकता है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में अधोसंरचना मद के पांच करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हैं। इसके अलावा निकाय मद से भी बड़ी संख्या में विकास कार्य संचालित हो रहे हैं। इन कार्यों का क्रियान्वयन केवल एक उप अभियंता के भरोसे संभव नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका के सेटअप में एसडीओ सहायक अभियंता का एक पद तथा उप अभियंता के चार पद स्वीकृत हैं। अध्यक्ष श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि नगर पालिका में प्लेसमेंट कर्मचारियों के 57 पद स्वीकृत हैं, लेकिन कार्यों की अधिकता को देखते हुए कम से कम 15 अतिरिक्त प्लेसमेंट कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कर्मचारियों की कमी के कारण विकास कार्यों और नगर पालिका की व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने प्रभारी मंत्री से आग्रह किया है कि नगर पालिका परिषद सूरजपुर में 02 उप अभियंताओं की नियुक्ति एवं 15 प्लेसमेंट कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति प्राथमिकता के साथ प्रदान करने की कृपा करें, ताकि विकास कार्यों को गति मिलने के साथ नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों का बेहतर संचालन हो सके।

जिले के स्कूलों में पुलिस ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम

छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को किया गया जागरूक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ह्लसाइबर जागृति अभियानह्लह्व के तहत जिले में पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन के मार्गदर्शन में बुधवार को जिलेभर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना-चौकी क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा

स्कूलों, सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर शिक्षकों एवं नागरिकों को ह्लमैं जागरूक हूँ, साइबर क्राइम से मुक्त हूँह्व संदेश के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक साइबर सुरक्षा संबंधी सेल्फी ली और उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। स्कूली बच्चों को भी इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है ताकि वे भी अपने अभिभावकों को इस अभियान से अवगत कराकर साइबर सुरक्षा की सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। सेल्फी के माध्यम से साइबर जागरूकता का संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। एक व्यक्ति द्वारा साइबर सुरक्षा की सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने से उसके मित्र, परिचित एवं सोशल मीडिया से जुड़े अन्य लोग भी प्रेरित होकर ऐसी सेल्फी लेने और उसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे है। इस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाला यह अभियान साइबर जागरूकता को वृहद स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य है कि साइबर अपराधों से बचाव के प्रति प्रत्येक नागरिक सजग एवं जागरूक बने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। साइबर सुरक्षा की सेल्फी अब केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता का संदेश बनकर सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बना रही है।

तुलसीदास : लोकभाषा में रामभक्ति और भारतीय जीवन-दर्शन के अमर साधक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

राज नारायण द्विवेदी

भारतीय संत परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान केवल एक महान कवि के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे लोकनायक संत के रूप में है, जिन्होंने श्रीराम के चरित्र और रामभक्ति को जन-जन के जीवन का हिस्सा बना दिया। हिन्दू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2026 में यह पावन अवसर 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। तुलसीदास का स्मरण वस्तुतः उस भारतीय लोकचेतना का स्मरण है, जिसमें धर्म केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति रहा है। मेरे लिए तुलसीदास और रामचरितमानस का संबंध केवल पुस्तकीय या धार्मिक नहीं है। मैंने बचपन से अपने गांव में रामचरितमानस का पाठ होते देखा है। ग्रामीण परिवेश में पला-बढ़ा होने के कारण मैंने बहुत

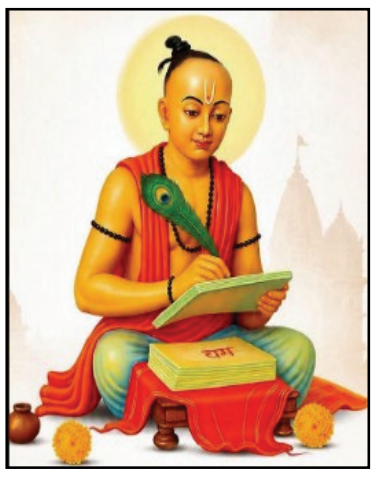

निकट से अनुभव किया है कि गांव के लोगों के जीवन में मानस किस प्रकार रचा-बसा है। वहां लोग सामान्य बातचीत में भी अवसर के अनुरूप रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों का उल्लेख कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा में प्रतिष्ठित रामकथा को अवधी जैसी लोकभाषा में प्रस्तुत करके उसे घर-घर पहुंचा दिया। रामचरितमानस केवल राम की कथा नहीं है; यह परिवार, समाज, कर्तव्य, त्याग, मयार्दा, सेवा, करुणा और लोककल्याण का जीवन-दर्शन है। तुलसीदास की दूसरी अत्यंत लोकप्रिय रचना ह्यहनुमान चालीसाह्व है। हनुमानजी के माध्यम से उन्होंने शक्ति, बुद्धि, विनम्रता, सेवा और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया। आज भी करोड़ों लोग श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं। तुलसीदास जयंती पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि केवल मानस का पाठ करना नहीं, बल्कि मानस के जीवन-मूल्यों को समझना और आचरण में उतारना है। तुलसीदास ने रामभक्ति को मंदिरों की सीमाओं से निकालकर लोकजीवन की सांसों में बसा दिया। यही कारण है कि आज सदियां बीत जाने के बाद भी गांव की चौपाल से लेकर घर के पूजा-कक्ष तक, बुजुर्ग की स्मृति से लेकर बच्चे के कंठ तक–रामचरितमानस जीवित है।

बारिश के कारण कन्हर नदी उफान पर तो कई घर हुए क्षतिग्रस्त

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजगंज। नगर पालिका क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई गरीब परिवारों को आर्थिक छती का सामना करना पड़ा। वही कन्हर नदी तेज ऊफान पर है। जिसके कारण कई वार्डों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 13 में मंगलवार सुबह एक मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के वक्त घर के अंदर मौजूद

दो बेटियां और एक बेटा बाल-बाल बच गए। बच्चों ने मकान गिरने का अंदेशा होते ही समय रहते घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उनके बाहर निकलने के कुछ ही समय के बाद मकान गिर गया। उक्त मकान हुजू भुइयां का बताया जा रहा है घटना के समय बच्चों के माता-पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। वही वार्ड क्रमांक 15 स्थित पहाड़ी माई मंदिर के पास वर्षों पुराना महुआ का पेड़ अचानक एक मकान के ऊपर जा गिरा।

सरगुजा ओलम्पिक में हिस्सा लेने का मौका, 29 अगस्त तक करें पंजीयन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष में भी सरगुजा ओलम्पिक 2026-27 हेतु पंजीयन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों पद्धति से किये जाने जाने की सुविधा प्रदान किया गया है। ऑफलाईन प्राप्त आवेदनो को संबंधित विकासखण्डो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के माध्यम से ऑनलाईन रूपांतरित किया जायेगा। आयोजन में कुल 12 खेलों की खेल प्रतियोगिताएं विकासखण्ड जिला एवं संभाग स्तर पर आयोजित की जायेगी। विकासखण्ड स्तरीय आयोजन सितम्बर 2026 के द्वितीय सप्ताह के मध्य आयोजित होना संभावित है। सरगुजा ओलम्पिक खेल का पंजीयन 29 अगस्त 2026 तक किया जाना है। प्रतियोगिता तीन चरण में विकासखण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय, एवं संभाग स्तरीय आयोजित की जायेगी विकासखण्ड स्तर पर पंजीयन दिये गए लिंक में अथवा ऑफलाईन विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय/जनपद कार्यालय/नगर पंचायत अथवा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला कार्यालय के माध्यम से किया जा सकेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विकासखण्ड स्तर पर एथलेटिक्स में 100 मी. 200 मी. 400 मी. दौड गोला फेंक, भाला फेंक, तवा फेंक, लम्बी कूद, उंची कूद, 4७100 रिले रेस, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबाल, कराते, कबड्डी, खो-खो, बालीवाल बास्केटबाल। हॉकी एवं कुश्ती के खिलाड़ी सीधे जिले स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। विकासखण्ड स्तर पर खेलों का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों द्वारा किया जायेगा व्यक्तिगत एवं दलीय खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अथवा दल जिला एवं संभाग स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता दो आयु वर्ग में होगा पहला 14 से 17 वर्ष बालक/बालिका एवं दूसरा 17 वर्ष से अधिक महिला/पुरूष होंगे। विकासखण्ड स्तर पर खिलाड़ियों को शील्ड ट्राफी से पुरस्कृत किया जायेगा। जिला स्तर पर व्यक्तिगत खेलों में विजेताओं को पहले से तीसरे स्थान तक क्रमशः 2000, 1500, एवं 1000 तथा दलीय खेल में क्रमशः 4000, 3000, एवं 2000 नगद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। संभाग स्तर पर व्यक्तिगत में क्रमशः 5000, 3000, एवं 2000 तथा दलीय खेलों में क्रमशः 10,000, 6,000 एवं 4,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित विकासखण्ड के जनपद कार्यालय, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं नगर पंचायत के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। अन्य जानकारी हेतु सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग सरगुजा के जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

मुंबई भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष शरद चिंतनकर के ओबीसी समाज संवाद दौरे की धूम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

ओबीसी समाज के विभिन्न घटकों को एक साथ लाकर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और विकास के सवालों पर सीधा संवाद साधने के उद्देश्य से मुंबई भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष शरद चिंतनकर ने ओबीसी समाज संवाद दौरे की धूम मचा दी है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष विधायक अमित साटम के मार्गदर्शन में मुंबई के विभिन्न विभागों में समाज बंधुओं से भेंट-मुलाकात, बैठकें और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और इस पहल को समाज से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ओबीसी समाज में माली, धनगर, कुम्हार, सुतार, लोहार, तेली, तांबोली, न्हावी, शिंपी, धोबी, वंजारी, आगरी, कोली जैसी सैकड़ों तथा अन्य अनेक जाति-जमातियों का समावेश है। इन विभिन्न समाज घटकों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और रोजगार संबंधी सवालों में कुछ मामलों में समानता होते हुए भी हर समाज की अपनी अलग-अलग कठिनाइयाँ और अपेक्षाएँ भी हैं। उन्हें जानने के लिए चिंतनकर के माध्यम से सीधे समाज संवाद पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरे के दौरान विभिन्न समाजों की संस्थाओं, मंडलों, पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकताओं, युवा कार्यकताओं और नागरिकों से संवाद किया जा रहा है। शिक्षा के अवसर, रोजगार व स्वरोजगार, कौशल विकास, व्यवसाय के लिए उपलब्ध योजनाएं, सरकारी रियायतें तथा सामाजिक विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस बीच, इस समाज संवाद दौरे को अधिक प्रभावी स्वरूप देने के लिए शनिवार, दिनांक 29 अगस्त को दादर स्थित मुंबई भाजपा के 'वसंत स्मृति' कार्यालय में ओबीसी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। सरकार की ओबीसी समाज के लिए मौजूद विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ लेने की प्रक्रिया और इन योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम घटक तक पहुँचाने के उद्देश्य से कार्यकताओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन से किसानों को मिल रहा लाभ

निःशुल्क मक्का बीज एवं कृषि विभाग के मार्गदर्शन से रमेश रजवाड़े ने 2 एकड़ में की मक्का की खेती

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन अंतर्गत मोटा अनाज योजना के माध्यम से जिले के किसानों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक सहयोग, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड अम्बिकापुर के ग्राम कृष्णापुर निवासी किसान रमेश रजवाड़े ने 2 एकड़ क्षेत्र में मक्का की खेती की है। ग्राम सेवक के माध्यम से उन्हें 2 एकड़ के लिए मक्का का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, जिसे उन्होंने खेत में निर्धारित कतार पद्धति से लगाया। वर्तमान में उनकी मक्का की फसल अच्छी स्थिति में है और खेत में फसल की बढ़वार देखकर वे उत्साहित हैं। रमेश रजवाड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष वे उड़द की खेती कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष शासन के मार्गदर्शन पर उन्होंने मक्का की खेती करने का निर्णय

लिया। कृषि विभाग द्वारा उन्हें मक्का बीज उपलब्ध कराने के साथ ही फसल को कतार में लगाने की जानकारी दी गई। उन्होंने खेत में मक्का की बुवाई के बाद समय-समय पर दवा का छिड़काव किया है और फसल की नियमित देखभाल कर रहे हैं।

किसान का अनुभव

रमेश रजवाड़े ने कहा, ₹कृषि विभाग के ग्राम सेवक एवं मैदानी अमले से खेती-किसानी के संबंध में समय-समय पर मार्गदर्शन मिल रहा है। इससे उन्हें फसल की देखभाल करने में सुविधा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि बेहतर फसल उत्पादन प्राप्त होगा और इससे मेरी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ₹ रमेश रजवाड़े ने निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने तथा किसानों को कृषि संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।

चिंतन

कब तक युद्ध की कीमत चुकाएगी अर्थव्यवस्था

युद्ध की पहली तस्वीर हमेशा मिसाइल, टैंक और सैनिकों की होती है, लेकिन उसकी सबसे लंबी और गहरी मार अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। रूस-यूक्रेन युद्ध में अब औद्योगिक प्रतिष्ठान और ऊर्जा ढांचा निशाने पर हैं। दूसरी ओर अमेरिका-इजराइल और ईरान के संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया है कि किसी एक क्षेत्र में युद्ध की आग भड़कने पर उसकी लपटें तेल, गैस, जहाजरानी, महंगाई और वैश्विक व्यापार तक पहुंच सकती हैं। हाल के महीनों में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, जबकि यह मार्ग दुनिया के करीब पांचवें हिस्से के तेल और एलएनजी कारोबार के लिए अहम है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी चेताया है कि युद्ध के कारण तेल बाजार पर पड़ा झटका वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम बन सकता है। इसी बीच यूक्रेन के क्रिवी रिह शहर में भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलरमित्तल के स्टील प्लांट पर रूसी मिसाइल हमला बेहद गंभीर संकेत है। हमले में दो लोगों की मौत और 13 कर्मचारियों व ठेकेदारों के घायल होने की खबर है। प्लांट की ऊर्जा व्यवस्था और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़े अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचा और उत्पादन का कुछ काम रोकना पड़ा। यह सिर्फ एक फैक्ट्री पर हमला नहीं है, बल्कि उस आर्थिक ढांचे पर प्रहार है जिसके सहारे किसी देश की उत्पादन क्षमता खड़ी होती है। स्टील को आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सड़कें बनानी हों, पुल खड़े करने हों, रेलवे का विस्तार करना हो, वाहन बनाने हों या रक्षा उपकरण तैयार करने हों। हर जगह स्टील की जरूरत है। इसलिए किसी बड़े स्टील संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रभावित होना केवल कंपनी के नुकसान तक सीमित नहीं रहता। इसके साथ कच्चे माल की आपूर्ति, परिवहन, रोजगार, निर्यात और हजारों दूसरी औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। युद्ध जब कारखाने तक पहुंचता है तो उसकी आर्थिक कीमत कई गुना बढ़ जाती है। सबसे चिंता की बात यह है कि आर्थिक ढांचा अब युद्ध की रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। आर्सेलर मित्तल के इस संयंत्र को 2022 में भी निशाना बनाया गया था। यानी चार साल बाद भी औद्योगिक प्रतिष्ठान सुरक्षित नहीं हैं। एक मिसाइल कुछ क्षणों में उस उत्पादन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे तैयार करने में वर्षों और अरबों रुपये लगते हैं। इसके बाद पुनर्निर्माण का बोझ भी उसी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ता है, जो पहले ही युद्ध से कमजोर हो चुकी होती है। भारतीय कंपनियों के लिए भी यह एक बड़ी चेतावनी है। वैश्विक निवेश के दौर में कंपनियां नए बाजारों और संसाधनों की तलाश में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच रही हैं, लेकिन अब निवेश का फैसला केवल बाजार और मुनाफे के आधार पर नहीं हो सकता। राजनीतिक स्थिरता, युद्ध का जोखिम, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्ग और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती भी निवेश के जरूरी पैमाने होने चाहिए। विडंबना यह है कि युद्ध लड़ने वाले देश सैन्य जीत का दावा कर सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था अक्सर ऐसी जीत की सबसे बड़ी कीमत चुकाती है। आम नागरिक के लिए युद्ध का मतलब नक्शे पर बदलती सीमाएं नहीं, बल्कि महंगा ईंधन, महंगी चीजें, असुरक्षित रोजगार और अनिश्चित भविष्य होता है। युद्ध कुछ घंटे में अर्थव्यवस्था की दशकों की मेहनत को मिटा सकता है। आखिर कब तक अर्थव्यवस्था युद्ध की कीमत चुकाती रहेगी। इसलिए बेहतर है कि सभी समाधान कूटनीति, संवाद और वार्ता से निकालें जाएं, ताकि अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे।

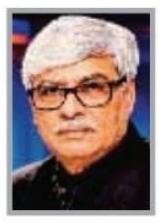

नई बहस

ओमकार चौधरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल कर देश की आंतरिक सुरक्षा की बदलती तस्वीर पर गंभीर बहस छेड़ दी है। बंदूक उठाने वाला नक्सलवाद कमजोर पड़ा है, लेकिन उससे जुड़ी हिंसक और अराजक मानसिकता के नए रूप सामने आने की आशंका जताई गई है। ऐसे में आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, 'अर्बन नक्सल' और 'दिमागी नक्सल' के बीच अंतर समझना जरूरी हो जाता है। खासकर डिजिटल दौर में विचार, दुष्प्रचार और सोशल मीडिया के जरिए असंतोष को हिंसा की ओर मोड़ने की चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के सामने नया सवाल खड़ा कर रही है।

दिमागी नक्सल क्यों बने नई चुनौती?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से एक ऐसा शब्द प्रयोग किया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक विमर्श में नई बहस छेड़ दी है- दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री का कहना था कि दशकों तक देश के बड़े भूभाग को हिंसा की गिरफ्त में रखने वाला सशस्त्र नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन नक्सली मानसिकता समाप्त नहीं हुई है। उनके अनुसार हथियारबंद नक्सली जंगलों में परास्त हुए हैं, पर ऐसी विचारधारा वाले तत्व अब भी अवसर की तलाश में रहते हैं और हिंसा तथा अराजकता के रास्ते खोजते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे तत्वों को पहचानने और उन्हें अलग-थलग करने की आवश्यकता बताई।

प्रधानमंत्री ने यह बात किसी सामान्य राजनीतिक सभा में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कही। इसलिए सवाल स्वाभाविक है कि आखिर यह चुनौती कितनी गंभीर है? क्या भारत की आंतरिक सुरक्षा के खतरे का स्वरूप बदल रहा है? क्या बंदूक, बारूद और जंगलों में चलने वाले विद्रोह के कमजोर होने के बाद अब विचार, प्रचार, भ्रम, सामाजिक असंतोष और अराजक आंदोलनों के जरिए व्यवस्था को चुनौती देने का दौर शुरू हो रहा है? इस प्रश्न को समझने के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, अर्बन नक्सल और अब 'दिमागी नक्सल'। इन पांचों के बीच अंतर भी समझना होगा। भारत कई दशकों तक एक साथ अनेक आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से जूझता रहा है। आतंकवाद ने जम्मू-कश्मीर से पंजाब और दिल्ली से मुंबई तक देश को गहरे घाव दिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया। दूसरी तरफ नक्सलवाद ने मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में समानांतर हिंसक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की। पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में अलगाववाद की चुनौती रही। इन सभी चुनौतियों की प्रकृति अलग थी, लेकिन एक बात समान थी। भारतीय राज्य, संविधान और स्थापित व्यवस्था को चुनौती। आतंकवाद का सबसे प्रत्यक्ष रूप हिंसा है। उसका उद्देश्य भय उत्पन्न करके सरकार और समाज पर दबाव बनाना होता है। बम विस्फोट, सामूहिक हत्याएं, आत्मघाती हमले, अपहरण और सुरक्षा बलों पर हमले इसके हथियार रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी रणनीति में बड़ा परिवर्तन किया है। आतंकवादी ढांचे, वित्तीय नेटवर्क, सीमा पार प्रशिक्षण और घुसपैठ के विरुद्ध सुरक्षा तथा खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है। आतंकवाद समाप्त हो गया है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उसकी परिचालन क्षमता को कई स्तरों पर गंभीर चोट पहुंची है। नक्सलवाद की कहानी इससे अलग है। 1967 में नक्सलबाड़ी से निकला माओवादी आंदोलन धीरे-धीरे सशस्त्र विद्रोह में परिवर्तित हुआ और छत्तीसगढ़, झारखंड, उडीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के हिस्सों में इसका प्रभाव फैलता गया। एक समय देश के सौ से अधिक जिले किसी न किसी रूप में नक्सली हिंसा से प्रभावित माने जाते थे। जंगलों के भीतर नक्सली संगठन अपनी समानांतर सत्ता चलाते थे। वे पुलिसकर्मियों और सुरक्षाबलों की हत्या करते थे, सरकारी भवनों को उड़ाते थे, सड़क और रेल ढांचे को

निशाना बनाते थे और स्थानीय आबादी से जबरन धन वसूलते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2026 के संबोधन में कहा कि नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और चार दशकों तक देश के बड़े हिस्से तथा विशाल आबादी को बंदूक के भय में रखा। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य नागरिकों की रक्षा करते हुए 3,500 से अधिक पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने बलिदान दिया, लेकिन यहीं से प्रधानमंत्री की दूसरी चिंता शुरू होती है। हथियारबंद नक्सली पराजित हो गए हैं, लेकिन नक्सली मानसिकता अभी मौजूद है। ऐसे तत्व अवसर तलाश रहे हैं, हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। यही वह संदर्भ है जिसमें दिमागी नक्सल शब्द सामने आया। सामान्यतः इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता रहा जो स्वयं जंगलों में बंदूक लेकर न लड़ते हों, लेकिन माओवादी हिंसा अथवा उसके वैचारिक आधार के प्रति सहानुभूति रखते हों, उसे वैचारिक, बौद्धिक या प्रचारात्मक समर्थन देते हों अथवा व्यवस्था-विरोधी हिंसक आंदोलन को वैध ठहराने का प्रयास करते हों। हालांकि "अर्बन नक्सल" कोई स्पष्ट कानूनी श्रेणी नहीं है और इस शब्द के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। इसीलिए आज राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा, पुलिस चौकी अथवा जंगल का प्रश्न नहीं रह गई है। सूचना का क्षेत्र भी नया युद्धक्षेत्र बन चुका है। सामाजिक माध्यम, कूट-रचित वीडियो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री, दुष्प्रचार, झूठी सूचनाएं और संगठित प्रचार कुछ घंटों में लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी स्थानीय विवाद को राष्ट्रीय संघर्ष बनाया जा सकता है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, बेरोजगारी, परीक्षा, किसान, छात्र अथवा किसी अन्य वास्तविक शिकायत को लेकर पैदा हुए असंतोष में भ्रामक सूचनाएं मिलाकर उसे हिंसक दिशा में मोड़ना पहले की तुलना में कहीं आसान हो गया है। यही वह क्षेत्र है जहां "दिमागी नक्सल" की अवधारणा को केवल पुराने माओवाद के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यदि इसका आशय ऐसी मानसिकता से है जो लोकतांत्रिक असंतोष को हिंसक अराजकता में बदलना चाहती है, समाज के विभिन्न वर्गों को लगातार एक-दूसरे अथवा राज्य के विरुद्ध भड़काती है और संवैधानिक रास्ते के बजाय अव्यवस्था को परिवर्तन का माध्यम मानती है, तो यह वास्तव में आधुनिक आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौती है। पुराने नक्सलवाद को पहचानना अपेक्षाकृत आसान था। जंगल में हथियारबंद दस्ते थे, निश्चित संगठन थे, कमांडर थे, प्रशिक्षण शिविर थे और प्रभावित क्षेत्र थे। आतंकवादी की पहचान भी उसके संगठन, हथियार, वित्तीय नेटवर्क अथवा हिंसक कार्रवाई से की जा सकती थी। लेकिन विचार और दुष्प्रचार के क्षेत्र में काम करने वाले नेटवर्क को पहचानना कहीं कठिन है। वहां अपराध और विचार, असहमति और उकसावे, आंदोलन और अराजकता के बीच बहुत महीन अंतर होता है। इसलिए राज्य के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे उन नेटवर्कों पर निगरानी रखनी होगी जो हिंसा, अलगाववाद, आतंकवाद अथवा माओवादी विद्रोह के लिए वैचारिक और प्रचारात्मक वातावरण तैयार करते हैं। दूसरी तरफ उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार की आलोचना करने वाला प्रत्येक पत्रकार, छात्र, लेखक, बुद्धिजीवी, किसान नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता केवल असहमति के कारण संदेह के घेरे में न आ जाए। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ी है। नक्सली हिंसा को पीछे धकेला है। अलगाववादी नेटवर्क को भी गंभीर चुनौती मिली है। लेकिन इतिहास बताता है कि हिंसक विचारधाराएं केवल संगठन समाप्त होने से खत्म नहीं होतीं। वे स्वरूप बदलती हैं, नए मुद्दे तलाशती हैं, नई भाषा अपनाती हैं और नई पीढ़ी में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जलवायु परिवर्तन

एस एन वर्मा

विदेशी निवेश से ही पूरा होगा नेट-जीरो उत्सर्जन का सपना

ग्लासगो में आयोजित 26वें जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने घोषणा की थी कि वह वर्ष 2070 तक कार्बन-न्यूट्रल देश बन जाएगा। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए भारत को वर्ष 2070 तक लगभग 22.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी औसतन करीब 500 अरब डॉलर प्रतिवर्ष निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें लगभग 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय अंतराल अनुमानित है, जिसकी पूर्ति के लिए विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि जरूरी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर जैसी महंगी और नई तकनीकों के विकास के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग और वैश्विक पूंजी की भी आवश्यकता होगी। फिलहाल, सम्मेलन में किए गए वादे के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में 30 जून 2026 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर आधारित कुल 297.36 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित हो चुकी है। इसमें 288.58 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है। वर्ष 2015 में ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के माध्यम से इसके लिए मजबूत आधार तैयार किया गया था। इसमें 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 33-35 प्रतिशत की कमी और गैर-जीवाश्म संसाधनों पर आधारित विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया था। नेट जीरो का अर्थ आखिर क्या है? इसका सीधा मतलब है कि वातावरण में छोड़ी जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों और उनसे होने वाले अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना। देश में इसकी दिशा में काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र का बेला गांव इसका उदाहरण है। यहां कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई सरल लेकिन प्रभावशाली कदम उठाए गए। गांव में वृक्षारोपण अभियान के तहत 90 हजार से अधिक पेड़ लगाए गए, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद करते हैं। सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए त्योहारों और विवाह समारोहों जैसे अवसरों पर भी पौधरोपण अभियान चलाए गए। स्वच्छ खाना पकाने को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक लकड़ी से चलने वाले चूल्हों की जगह एलपीजी और सौर ऊर्जा आधारित विकल्प अपनाए गए। वर्तमान में भूटान और सूरीनाम दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जो कार्बन नेगेटिव हैं। यानी वे जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं, उससे अधिक मात्रा में कार्बन का अवशोषण करते हैं। दोनों देशों को अपनी कम जनसंख्या, सीमित औद्योगिक गतिविधियों और बड़े वन क्षेत्र का लाभ मिलता है।वैश्विक जलवायु संकट के बीच विकासशील देश भी उत्सर्जन कम करने में अपना योगदान दे रहे हैं। दुनिया के बड़े कार्बन उत्सर्जकों में शामिल भारत ने जलवायु संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। हालांकि, अन्य बड़े प्रदूषकों की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन काफी कम है। दुनिया की करीब 17 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जबकि वैश्विक उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी 7 प्रतिशत से भी कम है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए पांच सूत्रीय रणनीति 'पंचामृत' की घोषणा की थी। इसके तहत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना, ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना, एक अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करना और कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में 45 प्रतिशत तक कमी लाना शामिल है। इन लक्ष्यों के आधार पर भारत 2070 तक नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़ रहा है।भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्त जुटाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमीर देशों से जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की मांग की है। नीति आयोग की 'नेट जीरो' रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2070 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगभग 22.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। वित्त वर्ष 2014 से 2026 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 45.72 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। आर्थिक मदद और नई तकनीकों के बिना इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। विकसित देशों को तकनीकी विकास और जलवायु वित्त में नेतृत्व करना होगा। भारत को भी अपने ऊर्जा ढांचे में बदलाव के साथ नागरिकों की जीवनशैली में परिवर्तन लाने होंगे। सही रणनीति, पर्याप्त निवेश और वैश्विक सहयोग के साथ भारत वर्ष 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सद्गुरु के प्रति रखना चाहिए कृतज्ञता का

हमें हमेशा सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। दुनियावी तौर पर भी देखें कि अगर हमें कोई ऐसे इन्सान से मिला देता है, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, तो हम उस इनसान के एहसान को नहीं भूलते, इसी प्रकार सद्गुरु ने हमारा परिचय एक ऐसी दिव्य शक्ति से करवाया है जो हमारी हर हरकत से वाकिफ है और हमारे अंग-संग भी है। भगवान

संकलित

दर्शन

श्रीकृष्ण ने गीता में इसकी निशानी बताई कि जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती व हवा उड़ा नहीं सकती। निरंकार प्रभु के सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक होने की बात श्री रामचरित मानस में भी की गई है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना।आनन रहित सकल रस भोगी,बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी।। लेकिन यह बात हमारे जहन में रहे कि निरंकार प्रभु की सारी शक्तियों को संचालित व क्रियान्वित रूप देने वाला स्वयं सद्गुरु ही होता है, क्योंकि निरंकार, सद्गुरु में ही समाया होता है। निरंकार अपने आपमें एक विधान है, यह न्यायकारी है, निरंकार का नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म के फल से चाहकर भी नहीं बच सकते। सद्गुरु से रहित सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आचार्य मां विजानियात अर्थात मुझे ही जानो। हे अर्जुन! संसार में ब्रह्मवेत्ता महात्मा सदैव ही उपलब्ध रहते हैं अन्यथा ब्रह्मवेत्ता रहित संसार एक भयंकर नरक कुंड बन जाता।

छोड़ दें ऐसे स्थान, जहां नहीं मिलता सम्मान

चाणक्य ने अपनी नीतियों के द्वारा बताया है कि किन स्थानों पर अधिक समय तक रहना खतरे से खाली नहीं है जितना जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ देना चाहिए। चाणक्य नीति अनुसार जिस जगह पर आपका कोई मान सम्मान या आदर न करता है उस जगह पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए

संकलित

प्रेरणा

जितनी जल्दी हो सकें उसे त्याग देना चाहिए वरना इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर नौकरी के पर्याप्त साधन न हो वहां पर भी अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। चाणक्य नीति की मानें तो जिस जगह पर कोई नाते रिश्तेदार या अपना सगा न रहता है वहां अधिक समय तक रहने से व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है ऐसे में इस स्थान को भी त्याग देना बेहतर होगा। जिस जगह पर शिक्षा के कोई साधन न हो या फिर जहां शिक्षा का महत्व न हो। वहां पर भी नहीं रहना चाहिए जितनी जल्दी हो ऐसे स्थान को त्याग देना उचित है। चाणक्य की मानें तो जहां रहने वाले लोगों में कोई अच्छा गुण न हो, वहां भी अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए वरना हम भी उन्हीं के जैसे बन जाएंगे।

अंतर्मन

आज की पाती

आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान जरूरी

कितनी हैरानी और चकित करने वाली बात है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को देश की एक छोटी सी समस्या पर भी बयान देना पड़ रहा है। यह समस्या है देश में आवारा कुत्तों से आमजन को होने वाली परेशानी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने से जो परेशानी हो रही है, और इससे रैबीज से होने वाली लोगों की मौतों पर चिंता जताई है। जबकि इस पर राज्य सरकारों को चिंता नहीं, बल्कि चिंतन करना चाहिए। मीडिया भी इस समस्या के लिए गंभीरता दिखाता है और प्रशासन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन नेतागण व प्रशासन यह गंभीरता नहीं दिखाते। रैबीज की बीमारी जानलेवा भी बन सकती है। इसलिए समूह समाज को इसका ठोस समाधान तलाशना चाहिए। *– विनय कुमार, सोनीपत*

ट्रेंड

मेरी शुभकामनाएं

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां पाने वाले सभी नेताओं को बधाई। नवनियुक्त टीम में संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी स्तर से जुड़ाव का बेहतर मेल है। मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं। **-नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

लोकसेवक बड़ी भूमिका निभाएं

लोक सेवकों को पूरे सेवा भाव के साथ बड़ी भूमिका निभानी चाहिए और लोगों के अनुकूल तरीके से सेवाएं देनी चाहिए। अधिकारियों को नियमित रूप से लोगों से मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। **-राजनाथ सिंह,** रक्षामंत्री

लोकल को ग्लोबल बनाएं

जब हमारा धन विदेशों मे जाता है तो उसका एक हिस्सा हमारे खिलाफ ही आतंकवाद को भड़काने और भारत को अस्थिर करने में खर्च होता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि स्वदेशी को प्राथमिकता दें। लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में प्रयास करें और यह अभियान गांव में भी प्रारंभ हो सकता है। **-योगी आदित्यनाथ,** सीएम, यूपी

भूमि नीति लाएंगे

हमारी सरकार जल्द ही व्यापक निवेश और भूमि नीति पेश करेगी तथा किसानों से जबरन भूमि अधिग्रहण किए बिना उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराएगी। हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपनाए गए सफल मॉडल के आधार पर भूमि नीति में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। **-शुभेंदु अधिकारी,** सीएम, प. बंगाल

करंट अफेयर

होर्मुज पर ईरान-ओमान मिलकर वसूलेंगे टैक्स!

अमेरिका और इजरायल द्वारा मिलकर ईरान पर हमला किए जाने के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति तेजी के साथ बदली है। कभी सभी के लिए खुला रहने वाला होर्मुज स्ट्रेट आज केवल कुछ ही देशों के लिए चालू है। अब इस मामले पर एक अहम परिवर्तन हुआ है। होर्मुज के दोनों किनारों पर स्थित ईरान और ओमान ने इस समुद्री रास्ते को लेकर एक नया समझौता किया है। हालांकि, ईरान, अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बाद लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि वह होर्मुज पर फीस लगाने वाला है। वह इसे फीस नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला 'सर्विस टैक्स' करार देता है। आने-जाने वाले जहाजों को और अधिक सुविधा देने और टक्कर से बचाने के लिए ईरान और ओमान इस रास्ते पर शिपिंग लाइन का निर्माण करेंगे। इसका उद्देश्य जहाजों के बीच की टक्कर को रोकना होगा। दोनों देशों की तरफ से बताया गया कि इस समझौते का मुख्य लक्ष्य महीनों से उलझे होर्मुज स्ट्रेट के विवाद को शांत करना और ग्लोबल ऊर्जा सप्लाई चैन को दोबारा से शुरू करना है। इस मामले पर अभी दोनों देश काम कर रहे हैं। तकनीकी चीजें साफ होने के बाद इस पर एक आधिकारिक दस्तावेज जारी किया जाएगा।

ऑफ बीट

केदारेश्वरनाथ मंदिर में बिस्कुट सब्जियों से सजता है शिवलिंग

सावन के पवित्र महीने में देशभर के शिव मंदिरों में भोलेनाथ का फूलों और बेलपत्र से विशेष श्रृंगार किया जाता है, लेकिन झारखंड के बोकारो का एक शिव मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के लिए खास चर्चा में है। कैंप-2 स्थित श्री श्री केदारेश्वर नाथ मृत्युंजय मंदिर में भगवान शिव का श्रृंगार फूलों के साथ गाजर, भिंडी, बैंगन, टमाटर, हरी सब्जियों, छाछ और यहां तक कि बिस्कुट से भी किया जाता है। पूजा के बाद इन सामग्रियों को श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। मंदिर के पुजारी निकेश कुमार शास्त्री ने बताया कि केदारेश्वर नाथ मृत्युंजय मंदिर का निर्माण उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को ध्यान में रखकर कराया गया है। पहले यहां एक छोटा मंदिर था, लेकिन करीब डेढ़ वर्ष पहले इसे भव्य स्वरूप दिया गया और मंदिर का निर्माण उड़ीसा के कारीगरों ने किया है। मंदिर परिसर में मां भगवती, राधा-कृष्ण, पंचमुखी हनुमान सहित कई देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। पुजारी के अनुसार, जो श्रद्धालु किसी कारणवश उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम नहीं जा पाते, उनके लिए यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। मंदिर की बनावट और धार्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम जैसा आध्यात्मिक अनुभव कराता है।

खबर संक्षेप

राधाकृष्णन 19 -20 को उत्तराखंड जाएंगे

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 और 20 अगस्त

2026 को उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) देहरादून का दौरा करेंगे। वहां वे 2025-27 बैच के आईएफएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे। 20 को मसूरी में आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के द्वितीय चरण के समापन करेंगे।

फरीदकोट डीसी कार्यालय को उड़ाने की धमकी

फरीदकोट। स्थानीय मिनी सचिवालय स्थित डिप्टी कमिश्नर

कार्यालय को मंगलवार दोपहर ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप है। डीएसपी तरलोचन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत डिप्टी कमिश्नर कार्यालय परिसर में सर्च आपरेशन शुरू किया।खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं गुनगुन महंत पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र / सुपुत्री/पत्नी कासी दास गाँव/शहर गोडीकला दिवानपुर, तहसील-पत्थगाँव, जिला- जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम- गुनगुन महंत (पुराना नाम) से बदल कर रिमुति महंत (नया नाम) रख लिया है।

नाबालिग पुत्री/पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक / पालक द्वारा प्रमाणित) मैं सविता महंत (माता/पिता/पालक का नाम)

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नि-काशी दास गाँव / शहर गोढीकला दिवानपुर, तहसील-पत्थगाँव, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम गुनगुन महंत (पुराना नाम) से बदल कर स्मृति महंत (नया नाम) रख लिया है।

माता/पिता/पालक के हस्ताक्षर

[redacted]

न्यायालय तहसीलदार, पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०)

रा०मा०क्र०/बी-121/2025-26

ग्राम-पत्थलगांव तह०-पत्थलगांव,

उद्घोषणा

एतद् द्वारा आम नगर पालिका परिषद, पत्थलगांव, को सूचित किया जाता है कि आवेदक शुभम शर्मा पिता रविकांत शर्मा साकिन ग्राम-पत्थलगांव थाना व तहसील-पत्थलगांव जिला-जशपुर के द्वारा प्रपत्र तीन में अवर्तित बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान-कलेक्टर महोदय एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय के माध्यम से जांच एवं प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन हेतु प्राप्त। आवेदन पत्र एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी पत्थलगांव के माध्यम से जाँच कर प्रतिवेदन हेतु प्राप्त। उक्त प्रकरण इस न्यायालय में इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 25.08.2026 को न्यायालयीन समय 11.00 बजे स्थान तहसीलदार पत्थलगांव के न्यायालय में होना नियत है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा/आपत्ति पेश करना हो, तो नियत तिथि एवं समय में मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से पेश कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक-10.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार

पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०)

पेपर लीक की घटनाओं को रोकने की शीर्ष अदालत में सुनवाई

आरोपी परिवारों की संपत्ति का आकलन करें कोर्ट ने केंद्र- राज्य सरकारों से मांगा जवाब

आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की मांग

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। याचिका में पेपर लीक में शामिल आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति की जांच कर उसे जब्त करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

■ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर पर यह कहा

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मंगलवार को अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है।

छात्रों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा

याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने, उनकी जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने में बार-बार नाकामी से छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 का हवाला दिया है। याचिका के मुताबिक, सरकारों की ओर से पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाए जाने के बावजूद व्यवस्था में अभी भी कई कमियां हैं। इनमें जांच और मुकदमे के लिए निश्चित समय सीमा का अभाव भी शामिल है।

दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजाएं लगातार चलें

याचिका में यह भी मांग की गई है कि पेपर लीक के अपराध में दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजाएं लगातार चलें, यानी एक के बाद एक लागू हों, न कि एक साथ। याचिकाकर्ता के मुताबिक इससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।

कानून आयोग से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर रिपोर्ट की मांग

याचिका में वैकल्पिक तौर पर कानून आयोग को पेपर लीक से निपटने के लिए दूसरे देशों में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से समयबद्ध जांच और मुकदमे की मांग को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित हो चुका है और इसमें पेपर लीक के खिलाफ कानून को और कड़ा किया गया है।

छात्रों पर गंभीर असर होगा

याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक का सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को होता है, जो महीनों और वर्षों तक मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परीक्षा रद्द होने या दोबारा होने से उनकी पढ़ाई और करियर की योजना प्रभावित होती है। इसका असर छात्रों के परिवारों पर भी पड़ता है। उन्हें लंबे समय तक तैयारी, कोचिंग और परीक्षा से जुड़े खर्च उठाने पड़ते हैं। कई परिवारों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। याचिका में दावा किया गया है कि पेपर लीक से पैदा होने वाले मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण छात्रों में गंभीर मानसिक परेशानियां भी बढ़ती हैं और कुछ मामलों में आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं।

भीड़ को नियंत्रित करने की थी फायरिंग

हलफनामे में जानकारी दी गई है कि हाथी चौक के समीप स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक सहायक उप-निरीक्षक ने अपनी 9-एमएम पिस्तौल से दो बार हवाई फायरिंग की थी। इस घटनाक्रम में तीन आंदोलनकारियों को हल्की चोटें पहुंचीं। राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इन व्यक्तियों की चोटों का गोलीबारी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वेफायरिंग वाले स्थान पर मौजूद ही नहीं थे।

पुलिस महानिदेशक ने दिशा-निर्देश जारी किए

पुलिस विभाग ने यह स्वीकार किया कि एके -47 विशेष अभियानों के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लाटून-स्तर का हथियार है, जिसे सामान्य कानून-व्यवस्था संभालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

उग्र भीड़ और हिंसा के पीछे उपद्रवी

शुरुआत में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन पूरी तरह अनुशासित और शांत था। हालांकि, बाद में कुछ अराजक और उपद्रवी तत्व भीड़ में घुस आए, जिसके कारण स्थिति हिंसक हो गई और पथराव व तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। इस हिंसा और उपद्रव में कानून-व्यवस्था संभाल रहे करीब 157 पुलिसकर्मी और 7 अन्य शासकीय कर्मचारी चोटिल हुए।

बिहार सरकार का हलफनामा

पुलिस ने हवा में चलाई थी एके-47 से 4 चक्र गोलियां

पटना। बिहार में छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा अनुचित और अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के आरोपों पर राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है।राज्य सरकार ने पुलिस बर्बरता के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान किसी भी तरह की अत्यधिक या असंगत ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया।हलफनामे में सिवान की घटना का जिक्र करते हुए बिहार सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ में घिरे एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने बचाव में अपने एके -47 हथियार से हवा में 4 चक्र गोलियां चलाई थीं। सरकार ने अदालत को बताया कि गोलियों से कोई भी व्यक्ति या प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ है।हालांकि, कानून-व्यवस्था जैसी स्थिति में इस प्रकार के असॉल्ट हथियार के अनधिकृत उपयोग को अनुचित आचरण मानते हुए संबंधित सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

अवैध संपत्ति जब्त की जाए

याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक करने वालों और इस तरह के अपराध में शामिल लोगों की पूरी संपत्ति का आकलन किया जाना चाहिए। इसमें उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की भी जांच करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि जांच में अवैध संपत्ति या अपराध से अर्जित धन का पता चलता है तो भ्रष्टाचार निवारण कानून, मनी लॉन्ड्रिंग कानून, बेनामी संपत्ति कानून और ब्लैक मनी कानून के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

रिजिजू ने दीपके पर पहले दिखाया नरम रुख, फिर सवाल भी उठाए

वह हमारा ही लड़का, बौद्ध है, आंदोलन को राजनीतिक बना दिया

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर सवाल उठाए हैं। रिजिजू ने उनकी छात्र के रूप में पहचान

पर भी सवाल किया। उन्होंने दीपके के लिए नरम रुख दिखाते हुए उन्हें अपना ही लड़का बताया। सीजेपी के बैनर तले जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन हुआ था।

इसके चलते पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। रिजिजू ने एक इंटरव्यू में दीपके और उनके आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। रिजिजू से जब छात्रों की शिक्षा क्षेत्र में सुधार से जुड़ी मांगों और जेन-जी आंदोलन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माना कि छात्रों की चिंताएं जायज हैं। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है।

छात्रों की आड़ में विपक्ष रोटियां सेंक रहे...

रिजिजू ने विपक्षी दलों और खास तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वे राजनीतिक दल हार जाते हैं, तो वे छात्रों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाकर रखी और किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। विपक्ष सरकार पर छात्रों के दमन की झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है।

आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया

युवाओं के बीच पहचान बना चुके दीपके का नाम लेते हुए रिजिजू ने कहा कि दीपके महाराष्ट्र से बौद्ध है। इसके बाद उन्होंने दीपके के छात्र होने पर सवाल उठाते हुए कहा, लेकिन वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है, वो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। वो छात्र कैसे हो गया?

कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु

प्रयागराज। यहां मंगलवार को श्रावण के पवित्र महीने के दौरान लोग 'कलश यात्रा' में भाग लेते हुए।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद

विफल रही बात, हम नहीं देंगे मस्जिद के लिए एक इंच भूमि

एजेंसी ▶▶ मथुरा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही सुलह-समझौते की कोशिशें एक बार फिर नाकाम साबित हुई हैं। मथुरा के सुलह समझौता केंद्र में मंगलवार को होने वाली दूसरी वार्ता मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति के कारण विफल हो गई। मुस्लिम पक्ष के न आने पर कोर्ट ने पत्रावली पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस अहम विवाद की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त को की जाएगी।

उपस्थित नहीं हुआ मुस्लिम पक्ष

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को सुलह केंद्र में दूसरी सुनवाई तय थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष वहां उपस्थित नहीं हुआ। इससे पहले 7 अगस्त को भी दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई थी, जो पूरी तरह बेनतीजा रही थी।

तेजस्वी यादव पर जीतनराम मांझी का तीखा हमला

जुबान फिसलने पर तीखा तंज कसा, रात वाला उतरा नहीं था तो मुझे श्रद्धांजलि दी

एजेंसी ▶▶ पटना

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान फिसलने पर तीखा तंज कसा है। मांझी ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तेजस्वी का रात वाला उतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे श्रद्धांजलि दे दी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के सुप्रीमो मांझी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। उसमें आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव कथित रूप से दशरथ मांझी की जगह मांझी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी ने तेजस्वी यादव पर नशा करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने यादव पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर हालात नहीं सुधरें तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। मांझी ने पोस्ट में कहा कि लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहें हैं। नशा कुछ भी करा सकता है।

दशरथ की पुण्यतिथि पर सभा में बोले थे तेजस्वी

सोमवार को पटना स्थित आरजेडी के कार्यालय में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को तेजस्वी ने संबोधित किया। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और श्रद्धांजलि देते हुए गलती से दशरथ मांझी की जगह हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी का नाम ले लिया। उसी दौरान बगल में मौजूद आरजेडी नेताओं ने तेजस्वी को कहा कि वह गलत नाम ले रहे हैं।

महिला सुरक्षा सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

सोनभद्र। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सोनभद्र पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के दूसरे चरण के अंतर्गत जनपद में व्यापक एवं प्रभावी जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष न्यायालय तहसीलदार

स्थान पत्थलगांव

मामले का विषय

खाता बटवारा

मामला क्रमांक/अ-27/2025-26

विरुध

फूलमनिया

बृजमोहन वगैरह

दावा

1/ बृजमोहन पिता शनिराम,

2/अनिल लकड़ा पिता इन्दलसाय,

3/ सुनिल लकड़ा पिता इन्दलसाय,

4/ रामा पिता शनिराम,

5/ प्रकाशचंद पिता शनिराम,

सभी जाति उरांव, निवासी ग्राम/तहसील-पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ०ग०) आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मामले की सुनवाई तारीख 03.09.2026 को दिन के 11.00 बजे स्थान पत्थलगांव पर होगी। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप या मान्य प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उक्त तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे। नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर आपके विरूध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

तहसीलदार पत्थलगांव,

जिला जशपुर (छ०ग०) पत्थलगांव,

छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 15 जनवरी 2026

FORM-1

NOTICE TOBE PUBLISHED IN NEWSPAPER FORM 1, IRISH NETAM,S/W/D/O GOVIND NETAM, Village/City-SURAJGARH LUDEG, TEHSHIL-PATHALGAON, DISTRICT-JASHPUR, Chhatisgarh have changed my name form IRISH NETAM(Old name)to KRISH NETAM

In case of minor Son/Daughter NameChange (Attested by parents/guardian)1, (Father/Mother/Guardian name-GOVIND NETAM S/o,W/o RAMKUNWAR Father /mother/Guardian of KRISH NETAM (Son/Daughter Name), Village/City-SURAJGARH Tahsil-PATHALGAON District JASHPUR Chhattisgarh have changed my mionr son/Daughter name form IRISH NETAM(old name)to KRISH NETAM(new name)

Signature (parents/Guardian

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

रा०प्र०क०.ब-121/2025-26

ग्राम - अलखडीहा तहसील राजपुर

ईशतहार

एत्द द्वारा सर्वसाधारण आम जनता अलखडीहा को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमति पूनम कुजूर पति स्व. प्रदीप लकड़ा जाति उराव निवास ग्राम अलखडीहा थाना राजपुर राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अपनी सासु माँ स्व. अनस्तसिया मिंज पति स्व. पोखो लकड़ा का मृत्यु दिनॉक 15.03.2013 को मृत्यु हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 07/09/2026 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 18/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कायार्पालिक दण्डाधिकारी

राजपुर

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छग०)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र.ब/121 वर्ष

ग्राम-भैयाथान प.ह.न. 13

ईशतहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक भानु प्रताप सिंह पिता स्वःमाहामाया प्रताप सिंह जाति क्षत्रिय निवासी ग्राम भैयाथान. प.ह.न. 13 रा.नि.म. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता स्व माहामाया प्रताप सिंह का मृत्यू दिनांक 01/04/2004 को ग्राम भैयाथान में हुई है. अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पिता स्व.माहामाया प्रताप सिंह का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत भैयाथान को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 03/09/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी भैयाथान जिला - सूरजपुर (छ०ग०)

राजपत्र में प्रकाशन हेतू

प्रित कौशिक पिता अनुज कौशिक उम्र 8 वर्ष जाति गोड त्रि या धन्धापुर थाना व तहसील राजपुर जिला. बलरामपुर- राजपुर में हुआ) का निवासी है। तथा आधार कार्ड नम्बर 759924927082 में नाम त्रुटि वेश प्रिति कौशिक दर्ज हो गया है। तथा पुरुष के जगह पर महिला दर्ज हो गया है जबकी प्रित कौशिक (पुरुष है)

अनुज कौशिक पिता रामधनी कौशिक

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2026

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं संतोस (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र /सुपुत्री/पत्नी सुखनाथ, शहर/गाँव-दिवानपुर, तहसील-पत्थलगांव जिला जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम संतोस (पुराना नाम) से बदल कर संतोष टोप्पो (नया नाम) रख लिया है।

मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना का सीएम ने किया शुभारंभ

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर स्थित बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह सभागार से विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन धरा पर आयोजित प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के सम्मेलन को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पीआरडी जवानों से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा०) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)

नीलाम विज्ञापन

सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, कि मनेन्द्रगढ वनमण्डल के अधीनस्थ काष्ठागार जनकपुर में उपलब्ध पुराना ईमारती काष्ठ एवं पुराना जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि व समय में ई-ऑक्सन द्वारा निवर्तन किया जाना है, इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्सन में अवश्य भाग लेवे। ई-ऑक्सन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार जनकपुर से प्राप्त कर सकते है।

डिपो का नाम - काष्ठागार जनकपुर

नीलाम दिनांक -31-08-2026

नीलाम समय- प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ

क्र	प्रजाति	नये अविक्रित काष्ठ		पुराने अविक्रित काष्ठ			
		लट्ठा	बल्ली	लट्ठा		बल्ली	
		घ.मी.	नग	नग	घ०मी०	नग	घ.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागौन	0.000	0	77	4.428	995	16.626
2	साल	95.000	500	12621	1424.887	1942	61.248
3	साजा	0.000	0	19	1.547	3	0.088
4	धावड़ा	0.000	0	11	0.960	1	0.017
5	हल्दू,मुण्डी,बांसा	0.000	0	2	0.087	0	0.000
6	नीलगिरी	0.000	0	0	0.000	560	2.993
	योगः—	95.000	500	12730	1431.909	3501	80.972
7	मिश्रित जलाऊ	-		80 चट्टा पुराना			
योग :—		-		80 चट्टा पुराना			

टीप :-

1. केता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. केताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत E.M.D. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई.डी से लॉगईन करके देख सकते है।

वनमण्डलाधिकारी

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़

जी 262702842/3

नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने 'स्रोत महोत्सव 2026' एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, कृषि और समृद्धि की जीवनधारा हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने में प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिन नदियों ने हमारी सभ्यता को पोषित किया और हमें समृद्धि दी, उनका संरक्षण हम सभी का साझा दायित्व है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के ओमाया गार्डन में आयोजित ह्यस्रोत महोत्सव 2026ह्ल एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश की नदियों के उद्गम स्थलों एवं जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण, जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने तथा नदी संरक्षण को व्यापक जन अभियान का स्वरूप देना है। कार्यशाला में जल संरक्षण, नदी पुनरुद्धार और जल प्रबंधन से जुड़े विषय विशेषज्ञों के साथ राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के सदस्य तथा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा मंथन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा। इसी भावना के साथ राज्य सरकार नदियों के उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और जनभागीदारी के समन्वय से व्यापक कार्ययोजना पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। महानदी सहित प्रदेश की अनेक नदियों ने कृषि, आजीविका और सामाजिक जीवन को समृद्ध किया है। नदियों का अस्तित्व उनके उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के स्वास्थ्य पर निर्भर है। इसलिए नदी संरक्षण का कार्य केवल उसके प्रवाह क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। हमें नदी के स्रोत से लेकर उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समझकर संरक्षण की समग्र योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। स्रोत महोत्सव

में विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसे धरातल पर समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

पांच प्रमुख स्तंभों पर आगे बढ़ेगा नदी संरक्षण अभियान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में नदी संरक्षण के लिए मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जनभागीदारी और कार्ययोजना के पांच प्रमुख स्तंभों पर काम किया जाएगा। प्रत्येक नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से मानचित्रण किया जाएगा। नदी का उद्गम कहां है, उसके प्रवाह क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, भू-उपयोग में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं और किन कारणों से नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रभाव पड़ रहा है - इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक मानचित्रण और अध्ययन के आधार पर नदी के पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी। इसमें वन एवं वनस्पति संरक्षण, मृदा क्षरण की रोकथाम, पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, आवश्यकतानुसार नई जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण और भू-जल पुनर्भरण जैसे कार्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाजल हमारे नदी तंत्र और भू-जल का मूल आधार है। इसलिए बारिश के पानी को तेजी से बहकर निकल जाने देने के बजाय उसे अधिक से अधिक मात्रा में धरती के भीतर पहुंचाने के उपाय करने होंगे। इससे भू-जल स्तर में सुधार होगा, जल स्रोतों को पुनर्जीवन मिलेगा और नदियों में लंबे समय तक जल प्रवाह बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

नदी संरक्षण को बनाना होगा जन आंदोलन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संरक्षण का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। नदियों के किनारे बसे गांवों और वहां रहने वाले लोगों का नदी से सीधा संबंध है, इसलिए उन्हें नदी संरक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख भागीदार बनाना होगा। उन्होंने जिला स्तरीय समितियों के सदस्यों से कहा कि नदियों के किनारे बसे गांवों में स्थानीय समितियां गठित कर पंचायतों के सहयोग से नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्य आगे बढ़ाए जाएं। स्थानीय समुदाय को नदी की स्थिति, उसके महत्व और संरक्षण के उपायों की जानकारी दी जाए। जब समाज स्वयं अपनी नदी और जल स्रोतों के संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है, तब ऐसे प्रयास अधिक प्रभावी और स्थायी होते हैं। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि जल संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को सरल एवं सहज भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि तकनीक तभी सार्थक है, जब उसका लाभ धरातल पर दिखाई दे और आम नागरिक उसे समझकर अपने जीवन में अपना सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदियों ने पीढ़ियों से मानव जीवन को जल, भोजन और आजीविका प्रदान की है।

मंत्री राजवाड़े ने ली समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और हितग्राहियों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के निर्देश

रायपुर। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज मंत्रालय में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण, सियान गुड़ी एवं वृद्धाश्रमों में उपलब्ध सुविधाओं तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने सहायक उपकरणों के वितरण में तेजी लाने तथा सियान गुड़ी एवं वृद्धाश्रमों में भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

'लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण' के मूलमंत्र के साथ अधोसंरचना विकास को दे रहे नई गति : अरुण साव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

पिछले ढाई सालों में 12,666 करोड़ के 1572 कार्यों को मिली प्रशासकीय स्वीकृति, इनमें सड़कों के 1285, पुलों के 247 और भवन निर्माण के 42 कार्य शामिल

रायपुर। उपमुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के कार्यों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य का सबसे बड़ा निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के विकास का आधार है। सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण के साथ विभागीय कार्यों में तेजी और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए विभाग लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर-2023 में सरकार बनने के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी और अपर सचिव एस.एन.श्रीवास्तव भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रेस-कान्फ्रेंस में बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग को 12 हजार 666 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के कुल 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। इसमें सड़क निर्माण के 1285, पुलों के 247 और भवन निर्माण के 42 कार्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर-2023 से मार्च-2024 तक 80 कार्यों के लिए 551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 374 किमी लंबाई की 72 सड़कें, 6 पुल और दो भवन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ 70 लाख रुपए लागत के कुल 438 कार्यों के लिए की स्वीकृति दी गई। इनमें 1465 किमी लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा।

स्वास्थ्य मंत्री ने किया दृश्य संवाद 2026 का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट ह्यदृश्य संवाद 2026ह्ल का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में रायपुर के प्रेस फोटो जर्नलिस्टों के साथ-साथ प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में तस्वीरों के जरिए प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा तथा जनसरोकार से जुड़े विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। चार कैटेगरी में आयोजित प्रदर्शनी की ह्यप्रकृति एवं पर्यावरणह्ल कैटेगरी में प्रदर्शित तस्वीरों ने प्रदर्शनी स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य को साकार कर दिया। वहीं ह्यसंस्कृति एवं परंपराह्ल कैटेगरी की तस्वीरों में छत्तीसगढ़ की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की महक महसूस की जा सकती है। ह्यसमाचार एवं जनसरोकारह्ल कैटेगरी में फोटो जर्नलिस्टों की नजर से महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक सरोकारों को एक क्लिक में जीवंत रूप दिया गया है। इस वर्ष रायपुर प्रेस क्लब ने प्रदर्शनी को और व्यापक स्वरूप देते हुए प्रेस क्लब के गैर सदस्य प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों के लिए भी ओपन कैटेगरी में भागीदारी का अवसर दिया। इस श्रेणी में 35 से अधिक प्रतिभागियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं।

फोटोग्राफी चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम - जायसवाल

प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फोटो जर्नलिस्टों की

भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी केवल कैमरे से तस्वीर खींचने का काम नहीं, बल्कि एक पल को इतिहास के लिए सुरक्षित कर देने की कला और जिम्मेदारी है। खासतौर पर फोटो जर्नलिज्म में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होतीं। फोटो जर्नलिस्ट को घटनास्थल पर मौजूद रहकर बेहद कम समय में यह तय करना होता है कि कौन-सा क्षण महत्वपूर्ण है और उसे किस एंगल से कैमरे में कैद किया जाए। उन्होंने कहा कि एक अच्छी तस्वीर के पीछे तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सही समय की पहचान, सही एंगल और परिस्थितियों को समझने की दृष्टि भी जरूरी है। कई बार पत्रकार घटना को शब्दों में विस्तार से बताते हैं, लेकिन एक तस्वीर वही बात एक क्षण में लोगों तक पहुंचा देती है। यही फोटो जर्नलिज्म की ताकत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन सराहनीय पहल है। इससे वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्टों के अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचेंगे और युवा तथा शौकिया फोटोग्राफरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। उन्होंने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं दीं।

तस्वीर पत्रकारिता की अधूरी खबर को पूरा करती है - मोहन तिवारी

रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ह्यदृश्य संवादह्ल केवल एक फोटो प्रदर्शनी नहीं, बल्कि तस्वीरों के माध्यम से समाज और समय से संवाद करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता, फोटो जर्नलिस्ट साथियों के बिना अधूरी है।

एक जनवरी से राज्य के सभी अस्पतालों को डिजिटल करने का लक्ष्य लेकर करें काम: जायसवाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यशाला: छत्तीसगढ़ में 2.63 करोड़ नागरिकों के बने एबीएचए, 12 हजार स्वास्थ्य संस्थान जुड़े

रायपुर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यशाला का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में आयोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की मॉडल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव कार्यशाला में राज्य की डिजिटल हेल्थ प्रगति की विस्तृत जानकारी साझा की गई। कार्यशाला में बताया गया कि एबीडीएम का सबसे नागरिक-केंद्रित हिस्सा एबीएचए (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) है, जिसके जरिए नागरिक अपनी जांच रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन और अन्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी सहमति से डॉक्टरों के साथ साझा कर सकते हैं। राज्य में अब तक 2.63 करोड़ नागरिकों के एबीएचए बनाए जा चुके हैं।

डॉक्टरों और अस्पतालों की भी डिजिटल पहचान

स्वास्थ्य पेशेवरों के पंजीकरण के लिए बनी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री से राज्य में 34 हजार से अधिक स्वास्थ्य पेशेवर जुड़ चुके हैं, जबकि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के माध्यम से अस्पताल, क्लिनिक, लैब और ब्लड बैंक जैसे 12 हजार से अधिक स्वास्थ्य संस्थान नेटवर्क से जुड़ गए हैं।

क्लेम प्रोसेसिंग होगी आसान, कागजी निर्भरता घटेगी

कार्यशाला में कहा गया कि एबीडीएम-सक्षम एचएमआईएस के प्रभावी उपयोग से मरीजों का पूरा रिकॉर्ड—पंजीयन से लेकर उपचार और डिस्चार्ज तक—डिजिटल रूप में दर्ज होगा।

फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट मामले की सुनवाई के लिए बनेगा विशेष मेडिकल बोर्ड, त्वरित जांच कर दी जाएगी रिपोर्ट

समाज कल्याण मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ने ली संयुक्त बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। दिव्यांगजनों, उभयलिंगी समुदाय तथा अन्य अंतर्विभागीय विषयों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर में समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रकरणों की होगी त्वरित जांच

बैठक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 186 व्यक्तियों से संबंधित प्रकरणों की जांच सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप राज्य मेडिकल बोर्ड अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराए जाने पर चर्चा हुई। संबंधित व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर परीक्षण कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने तथा निर्धारित समयान्तराल में दिव्यांगता की भौतिक जांच के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के प्रकरणों की समीक्षा किए जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की जांच के लिए राज्य मेडिकल एवं संभागीय मेडिकल बोर्ड में परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया होगी सुगम

बैठक में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने, मेडिकल बोर्ड में विषय- विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष मेडिकल बोर्ड एवं दिव्यांगता परीक्षण शिविर आयोजित करने पर चर्चा की गई। पात्र दिव्यांगजनों को समयबद्ध रूप से प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अस्थायी एवं स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की स्थिति में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं लेने पर भी सहमति बनी।

उभयलिंगी समुदाय के कल्याण पर भी हुई चर्चा

बैठक में उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों के लिए राज्य की

सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी संबंधी सहायता तथा समय-सीमा में पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने पर चर्चा हुई। सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के लिए सहायता अनुदान संबंधी दिशा-निदेर्शों में आवश्यक सर्जरी को शामिल किए जाने तथा निर्धारित दरों में वर्तमान बाजार दर के अनुरूप संशोधन की कार्यवाही पर विचार किया गया। राज्य के शासकीय अस्पतालों में उभयलिंगी व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पृथक ट्रांसजेंडर क्लीनिक/वार्ड की व्यवस्था किए जाने पर भी चर्चा हुई।

नशामुक्ति केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर जोर

बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों की समीक्षा की गई। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में संचालित नशामुक्ति केंद्रों के पंजीयन तथा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशामुक्ति केंद्रों में उपचाररत व्यक्तियों को दी जा रही दवाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा केंद्रों के विस्तार एवं बेहतर संचालन पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, भिक्षुक, उभयलिंगी एवं नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं संस्थागत संरक्षण के लिए संचालित शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में निवासरत हितग्राहियों के स्वास्थ्य परीक्षण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक संजीव झा, समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नशामुक्ति हेतु नशे के व्यापारियों पर करें सख्त कार्रवाई : प्रभारी मंत्री

प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने ली विभागीय समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने बुधवार को यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा, कलेक्टर श्रीमती रेना जमील, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, डीएफओ विपुल अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मंत्री श्री बघेल ने विभागवार योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आमजन को शासन की योजनाओं का समयबद्ध लाभ दिलाने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री बघेल ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए चल रहे कृषक पंजीयन, एग्रीस्टैक पंजीयन, बारदाने की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी शुरू होने से पहले ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।

उन्होंने कहा कि कृषकों की सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार नवीन धान खरीदी केंद्र खोले जाने पर चर्चा की। उचित मूल्य दुकानों एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित एवं औचक निरीक्षण करने तथा अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने खरीफ सीजन के दौरान खाद बीज वितरण की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों के पंजीयन की जानकारी ली।

गौशालाओं में बेहतर व्यवस्था और पशुधन संरक्षण पर जोर

पशुधन विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने गौशाला एवं गौधाम में पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पशुधन के लिए प्राप्त राशि का उचित एवं प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों, पशुओं के नियमित टीकाकरण, पशु रोगों की रोकथाम एवं उपचार की व्यवस्था की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।।मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान मत्स्य बीज उत्पादन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने तथा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की समीक्षा करते हुए जिले में अब तक किए गए सोलर इंस्टॉलेशन की जानकारी ली। उन्होंने वेंडर चयन प्रक्रिया की भी समीक्षा की और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सुपोषण चौपाल, जिले में संचालित एवं स्वीकृत

आंगनबाड़ियों, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी ली गई। मंत्री ने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ियों के नियमित संचालन, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध कराने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा।।शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या, शिक्षकों की उपस्थिति, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा की स्थिति, स्कूल भवनों की स्थिति एवं शाला प्रवेशोत्सव की जानकारी ली गई। इसके अलावा न्योता भोज के भी नियमित आयोजन करवाने के निर्देश दिए।

मंत्री ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। नगरीय निकायों में जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति एवं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की स्थिति की समीक्षा की गई। स्वच्छता अभियान के तहत कचरा संग्रहण एवं उसके प्रबंधन की जानकारी लेते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के दौरान जिले में स्वीकृत आवासों, आवास आवंटन के बाद निर्माण की प्रगति, शौचालय निर्माण, नवीन शौचालय स्वीकृति एवं सामुदायिक शौचालयों की स्थिति की जानकारी ली गई। साथ ही वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।।आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम, छात्रावासों की स्थिति, भवनों एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। मंत्री ने लंबित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा छात्रावासों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने जिले में पेयजल आपूर्ति एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिले के सभी 543 गांवों में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वन विभाग की समीक्षा के दौरान व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पट्टों, वनोपज, पर्यटन विकास एवं वृक्षारोपण की प्रगति की जानकारी ली गई। मानव-हाथी द्वंद्व की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने हाथियों की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।।राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान फौती नामांतरण, अविवादित एवं विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार, भू-अर्जन, पट्टा वितरण एवं अभिलेख दुरुस्तीकरण सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली गई। मंत्री ने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करने तथा आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से बचाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा । इस दौरान उन्होंने जिले में नशीले पदार्थों की आवक एवं खपत को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री श्री बघेल ने नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने नशीले पदार्थों की जिले में होने वाली आवक के स्रोतों की जानकारी जुटाने तथा सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा। जिले में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात जागरूकता बढ़ाने तथा नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। मंत्री ने निर्मित किए जाने वाले नवीन सड़कों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की पहचान कर आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं नवीन पुलिया निर्माण, पैच रिपेयर सहित अन्य आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से कराने को कहा। इस दौरान मंत्री श्री बघेल ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

12 को वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत

प्रधान जिला न्यायाधीश ने समीक्षा बैठक में दिए तैयारियों के निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में दो दिवसीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के पहले दिन 18 अगस्त को अधिवक्ताओं के साथ तथा दूसरे दिन 19 अगस्त को विभिन्न शासकीय विभागों एवं बैंकिंग संस्थानों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें संबंधित न्यायिक अधिकारीगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एक्का ने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे न्यायालयों में वर्षों से लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों तथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के सार्थक प्रयासों से पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में मामलों का निपटारा संभव हो सकेगा, जिससे न्यायालयों पर लंबित प्रकरणों का भार भी कम होगा। बैठक में विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका तथा जिले में संचालित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को प्रीलिटिगेशन प्रकरण शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व पक्षकारों को समय रहते नोटिस की तामीली सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें अपने प्रकरणों के निराकरण की तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके। नोटिस तामीली में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी विचार-विमर्श कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए।बैठक में बैंक ऋण वसूली, विद्युत बिल बकाया एवं अन्य लेन-देन संबंधी प्रकरणों के त्वरित समाधान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नियमों के तहत उपलब्ध अधिकतम छूट एवं राहत का लाभ आम नागरिकों तथा पक्षकारों तक पहुँचाया जाए। प्रधान जिला न्यायाधीश ने आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी विभागों, अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों से बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि आम जनता को त्वरित, सुलभ एवं सर्वसम्मति से न्याय प्राप्त हो सके।

वन विभाग में ठेका पद्धति लागू करने की तैयारी पर वन कर्मचारी संघ का विरोध

ग्रामीणों और कर्मचारियों के हित प्रभावित होने की आशंका

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने वन विभाग में ठेका पद्धति लागू करने के कथित प्रयासों का कड़ा विरोध किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे ने विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि विभाग में बनाई जा रही नई विभागीय स्थानांतरण नीति तथा वन विभाग के फ्रंट लाइन स्टाफ की पदस्थापना एवं स्थानांतरण के लिए तैयार की जा रही नीति का उद्देश्य वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करना है। संघ के अनुसार छत्तीसगढ़ एक वन प्रधान राज्य है, जहां लाखों ग्रामीण और आदिवासी परिवारों की आजीविका जंगल एवं वनोपज पर निर्भर है। वन विभाग के प्रमुख कार्य जैसे वृक्षारोपण, नर्सरी प्रबंधन, कूप कटाई, वन सुरक्षा और जल संरक्षण कार्य स्थानीय स्तर पर वन कर्मचारियों की भूमिका पर निर्भर हैं। ऐसे में इन कार्यों में ठेका व्यवस्था लागू करने से ग्रामीणों और विभागीय कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रदेश अध्यक्ष श्री दुबे ने आरोप

लगाया कि यदि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग में ठेका पद्धति लागू की जाती है तो बाहरी ठेकेदार अपने लाभ के लिए मशीनों अथवा बाहरी मजदूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्थानीय ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार के अवसर कम होंगे और ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलने से बेरोजगारी एवं आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। संघ ने आशंका जताई कि इसका असर प्रदेश से होने वाले पलायन पर भी पड़ सकता है। संघ का कहना है कि वन विभाग के मैदानी कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर जंगलों की सुरक्षा करते हैं। ठेका पद्धति लागू होने से जंगल की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ने के साथ-साथ वन्यजीवों और वन संपदा की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।नसंघ ने वन विभाग के फ्रंट लाइन स्टाफ वनरक्षक बल की पदस्थापना, स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित नई विभागीय स्थानांतरण नीति का भी विरोध किया है। संघ ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक 3371/910/2019/10-1/1 दिनांक 18.10.2019 के माध्यम से पूर्व में स्वयं प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा वन विभाग के फ्रंट लाइन स्टाफ की पदस्थापना, स्थानांतरण हेतु शासन द्वारा किए गए विभागीय स्थानांतरण नीति के प्रावधानों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। आरोप है कि पूर्व निर्देशों और स्थापित व्यवस्थाओं की अनदेखी करते हुए फ्रंट लाइन स्टाफ के हितों के विपरीत नीतियां थोपी जा रही हैं, जिससे वन कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है।

नीति वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी

छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की ग्रामीण-विरोधी, वन विरोधी और कर्मचारी-विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने की बात कही है।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि ठेका पद्धति को वापस नहीं लिया गया तथा कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित नहीं रखा गया, तो संघ प्रदेश में कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होगा। संगठन कर्मचारियों के साथ-साथ वन एवं ग्रामीण हितों की रक्षा के लिए आगे भी अपनी आवाज मजबूती से उठाता रहेगा।

बारिश बनी आफत, ढहा मकान, बही पुलिया, कई गांवों का संपर्क प्रभावित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। क्षेत्र में एक सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है, कई ग्रामीण मार्ग कीचड़ में तब्दील हो गए हैं और जगह-जगह सड़क एवं पुलिया क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जून से अब तक क्षेत्र में 1043.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते क्षेत्र के कई गांवों में आवागमन की स्थिति बिगड़ गई है। मूसलाधार बारिश का असर कांतिपुर गांव की पंचायत सड़क पर भी देखने को मिला। तेज बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण पंचायत सड़क पर बनी पाइपलाइन पुलिया बह गई। पुलिया के बह जाने से सड़क का एक हिस्सा प्रभावित हो गया और ग्रामीणों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया बह जाने के बाद सड़क से आवागमन मुश्किल हो गया है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों और पैदल आने-जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और पंचायत से मौके का निरीक्षण कर जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुलिया की मरम्मत कराने की मांग की है।

15 जून से अब तक 1043.6 मिमी बारिश दर्ज

लगातार बारिश के बीच खैरा-कातीपुर गांव में एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। घटना के समय घर में छोटे बच्चों सहित पूरा परिवार मौजूद था। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। परंतु घर में रखा घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

उफान पर बरगा नदी, आवागमन प्रभावित

ग्राम पंचायत रसौकी के पास बरगा नदी तूफान पर बह रही है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बरगा नदी चांदनी बिहारपुर क्षेत्र को कोरिया जिले के रामगढ़, सोनहत और बैकुंठपुर क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग से जुड़ी है। नदी में तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को आवागमन में

परेशानी हो रही है। बारिश जारी रहने पर नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका से ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।

खोहीर, बैजनपाठ, लुल्ह और तेलाईपाठ की सड़कें बदहाल

लगातार बारिश से खोहीर, बैजनपाठ, लुल्ह, भूंडा, तेलाईपाठ सहित कई गांवों की कच्ची सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं। सड़क पर जगह-जगह पानी जमा होने और कीचड़ के कारण वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान इन मार्गों की हालत पहले से ही खराब रहती है, लेकिन इस बार एक सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। जरूरी काम से बाहर जाने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

पहुंचविहीन गांवों में पहले ही बांट दिया गया जून का चावल

बारिश के कारण आवागमन बाधित होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से खाद्यान्न की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। उमझर, रसौकी, खोहीर, बैजनपाठ, लुल्ह, भूंडा, तेलाईपाठ सहित आसपास के पहुंचविहीन गांवों में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से जून महीने का चावल पहले ही वितरित कर दिया गया है। लगातार बारिश से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से कांतिपुर में बही पुलिया की जल्द मरम्मत, क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों को दुरुस्त कराने, खैरा-कातीपुर के पीड़ित परिवार को राहत सहायता देने तथा नदी-नालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।

प्रशासन ने की सतर्कता की अपील

प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से उफनती नदी-नालों को पार नहीं करने और तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की गई है। विशेषकर बच्चों को नदी और नालों के आसपास नहीं जाने देने की सलाह दी गई है।

न्यायालय तहसीलदार मैनपाट, जिला-सरगुजा छ.ग.

रा.प्र.क्र.-202607020800029/31-27/25-26

सूचना पत्र

एतद द्वारा सूचित संबंधित ग्राम पंचायत पथरई, तहसील मैनपाट, जिला सरगुजा छ0ग0 को सूचित किया जाता है कि आवेदक कविता पति मुकेश तिवारी एवं अन्य 03. जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम गेरेसा, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पथरई स्थित भूमि कुल खसरा 10 कुल रकबा 4.959 हे0 भूमि शामिल खाते की भूमि है जिसपर आवेदकगण एवं अनावेदक नरेश तिवारी आ0 रामधनी एवं अन्य 07, सभी जाति ब्राहमण, का नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि में आवेदकगण एवं अनावेदक के मध्य 1/7 भाग में खाता विभाजन किये जाने हेतु छ0ग0 भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत आवेदनमय, बी-1, सहित पेश किया गया है।

उक्त संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः ब्रिजवसिया उर्फ मालती आ0 रामधनी, ग्राम चलता, तहसील सीतापुर, शुशीला आ0 रामधनी, ग्राम शंकरगढ़ हरगांव, तहसील सीतापुर, तारा आ0 रामधनी, ग्राम कामापुर, विस्डाबाजार छानवे, जिला मिर्जापुर, अनीता आ0 रामधनी, निवासी कल्याणपुर, तहसील लटोरी को सूचित किया जाता है कि पेशी दिनांक 27. 08.2026, दिन गुरूवार को न्यायालय तहसीलदार मैनपाट, जिला सरगुजा छ0ग0 में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रकरण एकपक्षिय कर दिया गया जाएगा जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

तहसीलदार
मैनपाट
जिला-सरगुजा(छ0ग0)

जिले के अस्पतालो में दें गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, निजी प्रैक्टिस से बनाएं दूरी : दयालदास

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बुधवार को यहां जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में जीवन दीप समिति साधारण सभा की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समिति के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आमजन को बेहतर और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जनसमुदाय की आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अस्पताल भवन एवं परिसर में आवश्यक निर्माण तथा मरम्मत कार्य, मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के विषयों पर विचार किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन

एवं कार्य अवधि में वृद्धि सहित अन्य आवश्यकताओं पर भी चर्चा हुई। विभिन्न एजेंडों पर विचार-विमर्श के उपरांत आवश्यक कार्यों की पूर्ति एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप योग्य कर्मचारियों को अनुमोदन प्राप्त कर कार्य पर रखने, चिकित्सकों की अस्पताल में नियमित उपस्थिति एवं निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शासकीय चिकित्सकों को जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की हिदायत देते हुए निजी प्रैक्टिस से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने मौसमी बीमारियों की दवाइयों की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित रखने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता राजवाड़े, मुरली मनोहर सोनी, राजेश्वर तिवारी, अजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटले, सीएमएचओ डॉ. कपिल पैकरा सहित जीवन दीप समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छत टपक रही, शेड और तिरपाल काम का नहीं

बारिश में कुछ वार्डों में भर्ती मरीजों को पानी से बचाने स्वजन कर रहे मशक्कत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बारिश शुरू होते ही उत्तर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छत टपक रही है। अस्पताल भवन की हालत वैसे भी जर्जर है। कई वार्डों में छत से टपकते पानी को रोकने ऊपर से शेड लगाए गए हैं, लेकिन हालात में बदलाव पूरी तरह से नहीं आ पाया है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल के लिए नए भवन की जरूरत महसूस की जा रही है। बारिश का पानी टपकने से मरीजों और उनके स्वजन के साथ ही यहां सेवा देने वाले चिकित्सकों और स्टाफ को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अस्पताल के 6 वार्ड वाले पुराने टीबी वार्ड की दुर्गति तो हो ही गई है, मुख्य भवन में भी टपकते पानी का नजारा देखने को मिल रहा है। टाइल्स की चिकनाई के कारण फर्श में फिसलन की स्थिति बन रही है। आए दिन मरीज और उनके संबंधी गिर रहे हैं। स्वच्छकों के द्वारा साफ-सफाई का ध्यान तो

रखा जा रहा है, लेकिन अनवरत मरीजों का आना-जाना लगे रहने से सफेद टाइल्स बदरंग नजर आ रहे हैं। खासकर बुजुर्ग, गंभीर मरीज और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी वाली है। टपकती छत के साथ दीवारों में नमी से भर्ती मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। एक मरीज के संबंधी कमलेश चौबे ने कहा अस्पताल की स्थिति खराब है, वार्ड में पानी टपक रहा है। बैठने के लिए जगह तलाशना पड़ रहा है। अस्पताल का यह भवन भगवान भरोसे है। पानी के निरंतर टपकने से छत से प्लास्टर का स्लैब कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। बिजली के बोर्ड तक पानी से तर हैं, करंट का भय बने रहता है। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसे हालातों का नजर आना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा अलार्म है।

इलेक्ट्रानिक सामान तक सुरक्षित नहीं-अस्पताल परिसर में स्थित सरगुजा संभाग के एमडीआर, टीबी चिकित्सालय भवन, जिला क्षय उन्मूलन केन्द्र में तो हालात ऐसे हैं कि वार्ड में भर्ती किए गए मरीजों को हटाने की नौबत बन रही है। टपकते पानी के कारण यहां रखे इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य सामान भी सुरक्षित नहीं हैं। बिजली के बोर्ड तक पानी से तर हो गए हैं, करंट का खतरा हर पल मंडरा रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि दो-तीन दिन से हो रही मूसलाधार बारिश में अच्छे से अच्छे नवनिर्मित मकान भी चूने की कगार पर हैं। रही बात 6 वार्ड के पुराने भवन की, तो यह पहले से ही जर्जर स्थिति में है। इसकी सूचना संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को भी दी गई है।

मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था-डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि, पिछले साल ही जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए सीजीएमएससी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने आधा-अधूरा काम किया। पानी टपकने से बचाने के लिए ऊपर शेड जैसा कुछ लगाया गया था, लेकिन उससे कोई फायदा पहुंचा कि नहीं, नहीं बोल सकते। उन्होंने स्वीकारा कि, वार्ड और भर्ती मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन इन्हें असुविधा न हो इस पर अस्पताल प्रशासन की नजर है। मरीजों के लिए बैकअप में आइसोलेशन वार्ड में व्यवस्था रखी गई है। थोड़ी भी कठिनाई की स्थिति में मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया है।

पुराने भवनों का पुख्ता मरम्मत जरूरी-मेडिकल कॉलेज अस्पताल संभाग का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। यहां सरगुजा संभाग के अलावा सीमावर्ती जिलों से भी मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में भवन की जर्जर स्थिति सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी है। हर साल बारिश में यही समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे रख-रखाव व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। समय रहते वार्डों के छत से पानी टपकने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई होती, तो ऐसे हालात नहीं बनते। मरीजों के संबंधियों ने कहा कि जर्जर भवनों की पुख्ता मरम्मत की ओर प्रशासन को ध्यान देना होगा, ताकि मरीजों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में इलाज की सुविधा मिल सके।

'शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं, अच्छा नागरिक बनना भी है'-टीएस सिंहदेव

एनएसयूआई के 'छात्र संवाद' कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री ने होलीक्रॉस के छात्रों से की सीधी बात

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। एनएसयूआई के छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने होलीक्रॉस स्कूल के सभाकक्ष में छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया और उनके सवालों के जवाब दिए।

देश और समाज के प्रति जेन-जी और जेन-अल्फा के विचारों को जानने तथा उनकी मांगों को आगे रखने के उद्देश्य से पूर्व उपमुख्यमंत्री की पहल पर सरगुजा एनएसयूआई ने इस संवाद शृंखला की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम पूर्णत: गैर-राजनैतिक है। इसकी पहली कड़ी में बीते 30 जुलाई को पूर्व उपमुख्यमंत्री ने माउंट लिटेरा स्कूल के छात्र-छात्राओं से संवाद किया था। होलीक्रॉस स्कूल में आयोजित संवाद में छात्रों ने जेन-जी के जंतर-मंतर आंदोलन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे की कमियों से लेकर अंबिकापुर शहर की सड़क और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था तक पर सवाल पूछे। कुछ छात्रों ने उनकी निजी रुचियों पर भी प्रश्न किए। एक छात्र ने पूछा कि वे कौन-सी किताबें पढ़ते हैं, तो दूसरे ने

ऑस्ट्रेलिया में की गई उनकी स्काईडाइविंग के बारे में जिज्ञासा जताई। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल ने बताया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री का यह छात्र संवाद कार्यक्रम आगे स्कूलों के साथ-साथ महाविद्यालयों में भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सतीश बारी, अंकित जायसवाल, ऋषिकेश मिश्रा, धीरज गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दिए जवाब

साहित्यिक रुचि पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें लाइट फिलॉसफी वाले लेखन पढ़ना पसंद है और वे स्वामी विवेकानंद के साहित्य का गहराई से अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा कि, एक राजनैतिक व्यक्ति होने के कारण आमजन से संवाद में अधिकांश समय देने के कारण साहित्य के लिए समय सीमित हो जाता है। आजकल सूचनाओं के लिए वे यूट्यूब का भी अधिक उपयोग करते हैं। शिक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'अच्छी शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि भविष्य का एक अच्छा नागरिक बनना भी है।' जेन-जी और जेन-अल्फा के सड़क पर उतरकर अपनी मांगें रखने को उन्होंने तकलीफदेह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों से सार्थक संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

इसलिए दिखते हैं स्वस्थ

स्वास्थ्य का राज सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि, वे योग नहीं करते लेकिन रोजाना सुबह घूमते हैं। बैडमिंटन खेलते हैं, और संतुलित आहार लेते हैं। इसलिए इस उम्र में भी आप लोगों को स्वस्थ्य दिखते हैं। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका नालम पोद्दार एवं शिक्षक आशीष अग्रवाल ने किया।

ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और सड़क के मुद्दे पर चर्चा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर की द्वितीय बैठक राजीव भवन, ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शंकर प्रजापति ने की। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी अरविंद सिंह गप्पू और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदरजीत सिंह धंजल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का मंच संचालन मीडिया प्रभारी धनमीत सिंह छाबड़ा ने किया।

बैठक में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्य जोड़ने पर जोर दिया गया। शहर की बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और सड़कों की खराब स्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले समय में सड़क की समस्या को लेकर एनएच और नगर निगम का घेराव करने तथा स्मार्ट

मीटर के विरोध में बिजली ऑफिस का घेराव करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में ब्लॉक प्रभारी अरविंद सिंह गप्पू ने कार्यकर्ताओं को विस्तृत निर्देश दिए। ब्लॉक कांग्रेस सचिव तीरथ चौधरी ने वोटर लिस्ट का अवलोकन कर उसमें त्रुटि सुधार करने की बात रखी।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदरजीत सिंह धन्जल ने सभी कार्यकर्ताओं की बातों को सम्मान देते हुए कहा कि आगामी कार्यक्रमों के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी से आवश्यक चर्चा की जाएगी। बैठक के अंत में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सदस्य रूबी जैन ने आभार व्यक्त किया। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय प्रभारी अमित वर्मा, कोषाध्यक्ष मेराज रंगरेज, मंडल अध्यक्ष बालेश्वर तिर्की, अमित सिन्हा, सोहन जायसवाल, गुरप्रीत सिद्धू, शंकरलाल सिंह, संजय गुप्ता, हनुमान सिंह, पवन सिंह, बनाफर केरकेट्टा, रोशन कन्नौजिया, त्रिवेणी यादव, अजर मंसूरी, शकीला सिद्दीकी, विजय बेग उपस्थित थे।

शराब के नशे में फावड़ा से पीटकर पति-पत्नी की हत्या

ग्राम बिसरपानी में दोहरा हत्याकांड, आरोपी फरार

छ.ग.फ्रंटलाइन कमलेश्वरपुर। सरगुजा जिले के थाना कमलेश्वरपुर, मैनपाट अंतर्गत ग्राम बिसरपानी मझवारपारा में शराब के नशे में हुए विवाद के बाद फावड़े से पीटकर एक पुरुष और एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, 18 अगस्त को शाम 7 से 8 बजे के बीच ग्राम बिसरपानी के मझवारपारा निवासी सोमारू मझवार के घर में यह घटना हुई। घर में मृतक बेन्जे बड़ा पिता तिहरु बड़ा 35 वर्ष और मृतिका नईहारो मझवार 32 वर्ष और उसका पति बाबूलाल मझवार निवासी बिसरपानी शराब के नशे में मौजूद थे। करीब आधे घंटे बाद तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई देखकर डर के कारण मकान मालिक सोमारू मझवार घर से भाग गया। 19 अगस्त को सुबह 10-11 बजे जब सोमारू मझवार वापस घर आया तो देखा कि घर के अंदर बेन्जे बडा और नईहारो मझवार का शव पड़ा हुआ है। दोनों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। जमीन पर फावड़ा से वार के निशान भी मिले हैं। प्राथमिक जांच में पुलिस को संदेह है कि मृतिका नईहारो के पति आरोपी बाबूलाल मझवार ने ही फावड़े से मारकर दोनों की हत्या की है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गांधी स्टेडियम को स्टंट जोन बनाने के मामले में केस दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के गांधी स्टेडियम ग्राउंड में युवकों द्वारा की जा रही खतरनाक स्टंटबाजी पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर की रिट याचिका और पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार कोतवाली थाना के सहायक उपनिरीक्षक विवेक कुमार पांडेय ने मामले में अपराध दर्ज कर लिया है।

बता दें कि, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कई युवक बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों पर समूह बनाकर स्टेडियम के अंदर लापरवाहीपूर्वक बाइक चलाते और खड़े होकर स्टंट करते दिख रहे थे। गांधी स्टेडियम सुबह-शाम घूमने-टहलने वाले लोगों के लिए प्रमुख जगह है। स्टंटबाजी के कारण वहां आने वाले नागरिकों को असुविधा हो रही थी और हादसे का खतरा भी बना हुआ था। वीडियो के आधार पर अज्ञात युवकों की पहचान के प्रयास में पुलिस लगी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 285 सार्वजनिक मार्ग में बाधा और धारा 125 लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर दी गई साइबर सुरक्षा की जानकारी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन और नोडल अधिकारी साइबर सेल एएसपी रितेश चौधरी के नेतृत्व में जिले में 'साइबर जागृति अभियान' का पहला सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के 6 स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस और साइबर टीम ने वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों की जानकारी दी। विशेष रूप से ओटीपी, यूपीआई, क्यूआर कोड, फर्जी लिंक, एपीके फाइल, फर्जी कस्टमर केयर नंबर, सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी प्रोफाइल, अनजान वीडियो कॉल, सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट पर फोकस किया गया। छात्र-छात्राओं से अनजान व्यक्ति के साथ गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की अपील की गई। साइबर अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई गई। बताया गया कि समय पर शिकायत करने से ठगी गई राशि को रोकने की संभावना बढ़ जाती है। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के प्राचार्यों में डॉ. राजकुमार यादव, प्राची गोयल, नवा बिहान से मंगल पांडेय, उप निरीक्षक अभय तिवारी, सहायक उप निरीक्षक परशुराम पैकरा, महिला थाना से सउनि गंभीर साय, महिला आरक्षक सविता मरावी, संगीता, आरक्षक राहुल केरकेट्टा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस मितान और साइबर वॉलंटियर टीम से अतुल गुप्ता, विक्की गुप्ता और राजकुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं ने प्रश्न पूछे और पुलिस टीम ने उनका समाधान किया।

मां महामाया मंदिर परिसर में आस्था का प्रतीक 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरा

बुधवार को सुबह 9 बजे हुई घटना, किसी को नहीं पहुंचा नुकसान

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश का असर पुराने वृक्षों के साथ ही मकानों में भी पड़ने लगा है। जहां कई कच्चे मकानों के ध्वस्त होने की खबर अंबिकापुर और सरगुजा संभाग से आ रही हैं, वहीं विशाल दशकों पुराने वृक्ष धराशाई हो रहे हैं। इसी क्रम में शहर के प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर परिसर में बुधवार की सुबह 100 साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी श्रद्धालु या मंदिर परिसर में मौजूद व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ।

जानकारी के मुताबिक, वाक्या सुबह करीब 9 बजे का है। इस दौरान काफी श्रद्धालु मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे, और रोजाना की भांति पुजारी मौजूद थे। इसी बीच अचानक मंदिर परिसर में लगा बरगद का पेड़ धराशाई हो गया, जो दशकों से जन आस्था का प्रतीक माना जाता था। अचानक तेज आवाज के साथ पेड़ जमीन पर गिरने से एक पल के लिए भक्तों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। घटना के समय मंदिर परिसर में कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन पेड़ खाली जगह पर गिरने के कारण बड़ा हादसा टल गया।

मंदिर के पुजारी सहित स्थानीय लोगों का कहना है कि, लगातार बरसात और जड़ों के कमजोर होने के कारण पेड़ गिरा होगा। मंदिर प्रबंधन और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटाने का काम शुरू कर रही है। वहीं बिजली विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि सरगुजांचल की आराध्य मां महामाया के दर्शन के लिए मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

युवक की मौत, सर्पदंश की संभावना

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के करंजी थाना अंतर्गत एक युवक ने अचानक पैर में असहनीय दर्द होने की बात मां से कही और कुछ देर बाद उसकी तबियत बिगड़ गई। अस्पताल लाते तक युवक की मौत हो गई। संभावना सर्पदंश की बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम बतरा निवासी किशन सारथी 29 वर्ष, बीती रात घर में सोया था, और तड़के 4 बजे उठकर मां से काम पर जाना है कहते हुए खाना बना देने के लिए कहा। कुछ देर बाद वह पैर में दर्द होना बताया, और उसके मुह से लार निकलने लगा। तबियत बिगड़ते देख स्वजन उसे आननफानन में मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

शादी का झांसा देकर 9 साल तक दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। महिलाओं से संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना गांधीनगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2016 से 15 अगस्त 2026 के बीच उसके जान-पहचान के युवक अभिषेक कुमार यादव ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी अब शादी करने से इंकार कर रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 516/26, धारा 69 बी.एन.एस. एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)1 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। दौरान विवेचना पुलिस टीम ने पीड़िता का कथन लेखबद्ध किया और आरोपी की पतासाजी शुरू की। पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपी अभिषेक यादव पिता रामनारायण यादव 31 वर्ष निवासी बड़सरा थाना भैयाथान, हाल मुकाम गांधीनगर बिजली ऑफिस गली को हिरासत में लिया। आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया, यहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय, सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर, महिला आरक्षक सरस्वती, आरक्षक राहुल सिंह, रमन मंडल सक्रिय रहे। पुलिस ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

ड्रंक एंड ड्राइव: मोटरसायकल और ई-रिक्शा चालक पर 20 हजार का जुर्माना

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सरगुजा पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर यातायात शाखा द्वारा चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 चालकों पर बड़ी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 डीबी 0613 का चालक अमरदीप लकड़ा पिता याकूब लकड़ा 35 वर्ष निवासी सीतापुर जांच में शराब के नशे में धुत्त मिला। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर नशे की पुष्टि हुई। इसी तरह ई-रिक्शा क्रमांक सीजी 15 डीवाई 1512 का चालक सैफ खान पिता लाल मोहम्मद 34 वर्ष निवासी दर्रीपारा भी शराब के नशे में मिला और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। दोनों चालकों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

यातायात नियमों का पालन करें-यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। आमजन से अपील है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। कार्रवाई में यातायात शाखा के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।

जिपा 2026 की विजेता फोटोग्राफी प्रदर्शनी मुंबई से पुणे पहुंची

छ.ग.फ्रंटलाइन मुंबई। ज़ाइन इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स, जिपा 2026 ने एक साल में 65 देशों से 10,000 से अधिक सबमिशन प्राप्त कर रिकॉर्ड बनाया। मुंबई के नेहरू सेंटर में सफल प्रदर्शनी के बाद अब यह प्रदर्शनी 5 से 11 अक्टूबर तक पुणे की वेसावर आर्ट गैलरी में लगेगी। इसमें फोटो पत्रकारिता, शहरी परिदृश्य और निर्णायक क्षण श्रेणियों की कृतियां प्रदर्शित होंगी। विजेता तस्वीरें क्रिएटिव ज़ाइन पत्रिका और वार्षिक पुरस्कार पुस्तक में भी प्रकाशित होंगी। कॉर्पोरेट वकील और फोटोग्राफर विवेक वर्मा और अली जोलग्रादि द्वारा सह स्थापित इस मंच पर 18 विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जिसका मूल्यांकन 16 स्दस्यीय स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय पैनल के द्वारा किया जाता है। जिपा 2026 की यह प्रदर्शनी 5 से 11 अक्टूबर तक पुणे की वेसावर आर्ट गैलरी में आयोजित की जाएगी।

अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर पीजी कॉलेज में ओरिएंटेशन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं के लिए अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर एक दिवसीय ओरिएंटेशन आयोजित हुआ। फाउंडेशन की प्रतिनिधि श्रीमोई नाथ ने आवेदन प्रक्रिया

और पात्रता की जानकारी दी। प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि पिछले वर्ष 215 छात्राओं को लाभ मिला था, इस वर्ष शत-प्रतिशत पात्र छात्राओं को लाभ दिलाने का लक्ष्य है। आईक्यूएसी को-ऑर्डिनेटर डॉ. उमेश पांडेय ने बताया कि छात्राओं की सहायता के लिए कॉलेज में नियमित हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. दीपक सिंह एवं डॉ. उमेश पांडेय ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर